● वर्ष-5

● अंक-213

रायपुर, गुरुवार
23 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर ...

चुनावी रैली में राहुल पर जमकर बरसे अमित शाह

बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दमदम में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है और राज्य में उसका कोई जनाधार नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेजी से मजबूत हो रही है और आने वाले चुनावों में बड़ा प्रदर्शन करेगी।

रैली के दौरान शाह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि वे केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा विकास और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव का समय आ गया है और जनता भाजपा के साथ खड़ी है। शाह के इस बयान से राज्य की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है।

रैली में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और राज्य को गुंडों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या राज्य में चार शादियों की छूट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, जिससे तीन तलाक और बहु-विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इसका समाधान कमल को वोट देने से मिलेगा।

इसके साथ ही शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बंगाल का मुख्यमंत्री कोई स्थानीय, बंगाली भाषा बोलने वाला व्यक्ति होगा और भाजपा कार्यकर्ता ही राज्य की बागडोर संभालेगा। रैली में उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं के खातों में हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए लागू किया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। अमित शाह ने यह भी वादा किया कि कोलकाता मेट्रो का तीन गुना विस्तार किया जाएगा और शहर के विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल के विकास और बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

अपनी पहली यात्रा पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार

बर्लिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आधिकारिक दौरे पर जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने बर्लिन में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत-जर्मनी संबंधों, भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव पर विस्तार से बात की।

रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि बर्लिन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत और जर्मनी के बीच लिविंग ब्रिज बताया और कहा कि हाल के वर्षों में यह समुदाय एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने भारत की तेज आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास को रेखांकित किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, अंतरिक्ष और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले सात दशकों में भारत और जर्मनी के संबंध हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। आज जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में 2,000 से अधिक जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं और जर्मनी की अग्रणी कंपनियां भारत के औद्योगिक विकास व मेक इन इंडिया अभियान को गति दे रही हैं। दूसरी ओर, कई भारतीय कंपनियां भी जर्मनी में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के राजनीतिक व कूटनीतिक संबंधों के द्वार भले ही

सरकारों के हाथ में हों, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों की असली मजबूती लोगों के आपसी जुड़ाव से तय होती है। उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा कि इस पुल को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका बेहद अहम है। राजनाथ सिंह ने बताया कि जर्मनी में भारतीयों की संख्या 3.7 लाख है और यह लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की उपलब्धियों और योगदान ने जर्मनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उनकी जर्मनी की पहली आधिकारिक यात्रा है और वह वहां के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक उपलब्धि है कि समय के साथ भारत और जर्मनी के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 भारत और जर्मनी के लिए विशेष है, क्योंकि इस वर्ष दोनों देशों के औपचारिक राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और जर्मनी केवल राजनीतिक और रणनीतिक संबंध ही साझा नहीं करते, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गहरा उत्साह और जुड़ाव है। राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें हम्बोल्ट विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।

कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि यह उनकी जर्मनी की पहली यात्रा है, जबकि वह अमेरिका सात से आठ बार जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वह दो बार अमेरिका जा चुके हैं। इस पर श्रोताओं के हंसने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि लोग क्यों हंस रहे हैं, जबकि वह तो सभी से मिलकर प्रसन्न हैं।

राजनाथ सिंह ने जर्मनी की वैश्विक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की सराहना करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जर्मनी का एक अलग सम्मान है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की इस सफलता में वहां के मूल निवासियों का बड़ा योगदान है, लेकिन भारतीय प्रवासी समुदाय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता।

राजनाथ ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी को लेकर कहा कि सरकार ने स्वदेश लौटना चाहने वालों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को वापस लाने के लिए विमानों की भी व्यवस्था की गई है और जरूरतमंद भारतीय नागरिक संबंधित भारतीय दूतावासों से संपर्क कर सकते हैं।

मणिपुर में हिंसा के विरोध में विभिन्न संगठनों ने बुलाया बंद

इंफाल। मणिपुर में जातीय हिंसा की तपिश और विभिन्न समुदायों के बीच पनपा आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बुधवार को राज्य के अलग-अलग जातीय संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद के कारण मणिपुर के कुल 16 में से 12 जिलों में सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी में बीते सात अप्रैल को हुए बम हमले के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) ने पांच दिवसीय बंद का आह्वान किया है। इस हमले में दो मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस बंद का इंफाल घाटी के सभी पांच जिलों में व्यापक असर देखा जा रहा है। इंफाल पश्चिम के सगोलबंद और पटसोई जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। यातायात पूरी तरह ठप होने से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं।

घाटी के साथ-साथ राज्य के पहाड़ी जिलों में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यूनाइटेड नागा काउंसिल की ओर से बुलाए गए तीन दिवसीय बंद का आज दूसरा दिन था। यह बंद 18 अप्रैल को उखरुल जिले में दो तंगखुल नागा व्यक्तियों की हत्या के विरोध में बुलाया गया है। नागा बहुल छह पहाड़ी जिलों में इस बंद का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। नोनी जिले और इंफाल पूर्व के याइंगांगपोकपी में बंद समर्थकों ने सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे केंद्रीय सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी काफी परेशानी आई।

उधर, चुराचांदपुर जिले में भी स्थिति अलग नहीं थी। जोमी समन्वय समिति के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों ने 13 घंटे के बंद का आह्वान किया। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के विधायक वुंगजागिन वाल्टे के लिए न्याय की मांग को लेकर किया गया। गौरतलब है कि मई 2023 में जातीय हिंसा की शुरुआत में एक उग्र भीड़ ने वाल्टे पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लंबे उपचार के बाद इसी साल फरवरी में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था।

प्रभावित जिलों में बंद का असर इतना गहरा था कि स्कूल, कॉलेज, बैंक और निजी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा और सार्वजनिक परिवहन के साधन सड़कों से नदारद रहे। केवल फार्मेसी और आपातकालीन सेवाओं को ही छूट दी गई थी।

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी

दोषियों को माफ नहीं करेगा भारत : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने पोस्ट में राहुल ने कहा कि देश इस कायराना हमले को कभी नहीं भूलेगा और दोषियों को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों के परिवारों का दुख पूरे देश का दुख है।

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पिछले साल पहलगाम में हुए हमले में जिन बहादुर लोगों ने अपनी

जान गंवाई, उनकी याद आज भी दिल को झकझोर देती है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की शहादत हमेशा देश की आत्मा में दर्ज रहेगी और भारत आतंक और नफरत फैलाने वाली ताकतों के सामने कभी नहीं झुकेगा।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 2025 में हुए इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश हमेशा उनके साथ खड़ा है।

इस दौरान खरगे ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट किया गया।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी ने केदारनाथ के कपाट खुलने पर दी बधाई

नईदिल्ली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के भव्य शुभारंभ और बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना का भव्य उत्सव करार दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा जगद्गुरु आदि शंकराचार्य,

रामानुजाचार्य और माध्वाचार्य जैसी महान विभूतियों की विरासत को आगे बढ़ाने वाली है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर प्रेषित अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि - देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार के दर्शन सहित चारों धामों की यह पावन यात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना का एक भव्य उत्सव है। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राओं से भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी थी। जगद्गुरु रामानुजाचार्य और जगद्गुरु माध्वाचार्य ने भी अपने धर्मविचारों को समृद्ध करने के लिए बद्रीनाथ की यात्रा की थी। आज भी हिमालय की गोद में विराजमान ये चारों धाम हमारी शाश्वत आस्था और विश्वास के दिव्य केंद्र हैं।

कांग्रेस के खून में सनातन विरोध : निशिकांत दुबे

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने बुधवार को नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ आरोपों को दोहराते हुए उन पर भारत को मुस्लिम राष्ट्र में बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में बाधा डालने

का आरोप लगाया, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को धमकी भरे पत्र लिखना भी शामिल था। 22 अप्रैल, 1951 के एक सरकारी नोट को साझा करते हुए, भाजपा नेता ने दावा किया कि नेहरू ने मंदिर के उद्घाटन को रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए। दुबे ने कहा कि बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। सरदार पटेल और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जनता के समर्थन से मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। दुबे ने आगे दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर मामले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली से माफी मांगी और संसद में भी इसी तरह की माफी मांगी।

ममता सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहीं, मोदी हारेंगे : केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि उन्होंने फोन पर उनसे बात की और पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि अभी ममता

दीदी से फोन पर बात हुई। मैंने उन्हें पूरी एकजुटता और समर्थन दिया। वह सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। मोदी जी हारेंगे, चाहे उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी संस्थानों का दुरुपयोग किया हो। केजरीवाल की ये टिप्पणियां पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आई हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कड़ी टक्कर दे रही है। उनकी ये टिप्पणी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर में प्रस्तावित रैली की अनुमति रद्द करने के एक दिन बाद आई है, जिससे तृणमूल कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यह फैसला 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले आया है, जिसमें भवानीपुर भी शामिल

नीतीश कुमार ने जेडीयू में किया बड़ा संगठनात्मक बदलाव

पटना। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के लिए एक नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है, जिसमें संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। नए संगठनात्मक ढांचे में 12 राष्ट्रीय महासचिवों और 8 सचिवों की नियुक्ति शामिल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली

इस नई टीम में, बेहद पिछड़े समुदाय से आने वाले पूर्व जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, गोपालगंज सांसद आलोक कुमार सुमन को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना और नेतृत्व का विस्तार करना है। नीतीश कुमार ने इस साल 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा सांसद बन गए। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उच्च सदन में उनका प्रवेश व्यापक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के अंत और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मार्ग प्रशस्त करने के संकेत के रूप में देखा गया।

कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में केसीआर पर नहीं होगी कार्रवाई

हैदराबाद। हैदराबाद में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और तीन अन्य को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को

निर्देश दिया कि पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आयोग कालेश्वरम परियोजना में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए गठित किया गया था। केसीआर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया था। उनका कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने और जिरह का मौका नहीं दिया गया। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि आयोग का गठन अवैध या असंवैधानिक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दिए गए हैं।

नारी सम्मान की पुकार में विपक्ष की पराजय

कांतिलाल मांडोत

देश की राजनीति के वर्तमान दौर में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनभावनाओं और राजनीतिक दृष्टिकोण का आईना बनकर सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन वास्तव में नारी सशक्तिकरण के साथ खड़ा है और कौन इस विषय को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। संसद में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से बयानबाजी और रणनीतियां सामने आईं उसने लोकतंत्र की परिपक्वता और दलों की मंशा दोनों को उजागर कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पीड़ा और प्रतिबद्धता के साथ देश को संबोधित किया वह केवल एक नेता का वक्तव्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नेतृत्व का संकेत था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो पाने का उन्हें दुख है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होगा बल्कि और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा यह दृष्टिकोण जनता के भीतर विश्वास पैदा करता है कि प्रयास सच्चे हैं और दिशा स्पष्ट है।

विपक्षी खेमे मेराहुल,प्रियंका और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे जैसे नेताओं की बैठकों और प्रेस वार्ताओं ने यह दर्शाया कि वे इस मुद्दे को जनहित की बजाय राजनीतिक अवसर के रूप में अधिक देख रहे हैं ।महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर स्पष्ट और ठोस समर्थन देने के बजाय उन्होंने शर्तों और संशोधनों की बात कर अपने रुख को कमजोर किया है। यह जनता के सामने उनकी प्राथमिकताओं को उजागर करता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अब यह कह रहा है कि पुराने विधेयक को वर्तमान सीटों पर लागू किया जाए लेकिन जब अवसर था तब उन्होंने उसी विधेयक को समर्थन क्यों नहीं दिया। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। जनता इस विरोधाभास को भलीभांति समझ रही है और यह स्थिति विपक्ष की

विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

परिसीमन के मुद्दे पर भी जिस प्रकार से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं है यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। लेकिन इसे क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक नुकसान के रूप में प्रस्तुत करना केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया और यह स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होती है।

इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा और एनडीए की रणनीति अधिक स्पष्ट और संगठित दिखाई देती है जहां एक ओर वे संसद में अपने प्रयासों के माध्यम से विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब वे जनता के बीच जाकर इस विषय को समझाने का संकल्प ले रहे हैं। यह सक्रियता और आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वे इस मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं।

विपक्ष द्वारा देशभर में अभियान चलाने और सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने की बात यह दर्शाती है कि वे संसद में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में असफल रहे अब वे सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की जागरूक जनता केवल नारों और आरोपों से प्रभावित नहीं होती वह कार्य और नीयत दोनों को परखती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिस प्रकार से परिवारवाद और स्वार्थी राजनीति का उल्लेख किया वह भारतीय राजनीति की एक पुरानी समस्या की ओर संकेत करता है ।जब निर्णय समाज के व्यापक हित की बजाय कुछ परिवारों के हित में लिए जाते हैं, तब विकास और समान अवसर बाधित होते हैं ।महिला आरक्षण जैसे विषय ऐसे ढांचे के लिए चुनौती बनते हैं क्योंकि यह नई नेतृत्व क्षमता को जन्म देता है और सत्ता के केंद्रीकरण को तोड़ता है।

इस पूरे प्रकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि आज की नारी केवल दर्शक नहीं है वह सक्रिय रूप से राजनीति और समाज को समझ रही है। वह यह देख रही है कि कौन उसके अधिकारों के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और कौन केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है।

सचिन तेंदुलकर बस्तर में ला रहे खेल क्रांति

■ सचिन तेंदुलकर बस्तर दौरे पर हैं. सचिन अपने फाउंडेशन की मदद से बस्तर के गांवों में 50 प्ले ग्राउंड तैयार करवा रहे हैं.

फाउंडेशन बना रहा 50 मैदान, स्कूली बच्चों के साथ खेलेंगे गेम

जगदलपुर। कभी नक्सलवाद से पहचान बनाने वाला बस्तर अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। जिस धरती पर कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। वहां अब खेल और विकास की आवाज बुलंद हुई है। इस बदलते बस्तर ने भारत रत्न और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बस्तर पहुंचना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि उस बदलाव की तस्वीर है, जहां डर की जगह अब सपनों ने ली है। सचिन यहां बच्चों के खेल भविष्य को संवारने के मिशन के साथ पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर ने बताया कि 50 स्कूल मैदानों को विकसित किया जाएगा। जहां बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। मैदान में प्रतियोगिताओं के जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इस पहल को मानदेशी फाउंडेशन और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। करीब 5 हजार से ज्यादा बच्चों को इस अभियान से सीधा लाभ मिलेगा। कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल जैसे खेलों के जरिए बस्तर के युवाओं को नई पहचान देने की तैयारी है- सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर

सचिन तेंदुलकर के आगमन की खबर सुनकर स्थानीय क्रिकेट प्रेमी और बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने सचिन की एक झलक पाने के लिए उमंग और जोश के साथ उनका स्वागत किया। सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के बल्ले पर ऑटोग्राफ भी दिए। जिसे पाकर मासूम चेहरों पर खुशी झलक उठी। ये पल बच्चों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा बन गया। वहीं बच्चों के साथ आए उनके अभिभावकों ने भी बस्तर में आए सचिन तेंदुलकर का स्वागत किया।

बस्तर की पहचान बदलेंगे सचिन

बदलते बस्तर में आज भारत रत्न और क्रिकेट जगत के महानायक सचिन तेंदुलकर का आगमन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बस्तर पहुंचना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की तस्वीर है, जहां डर की जगह अब सपनों ने ले ली है। सचिन यहां बच्चों के खेल भविष्य को संवारने के मिशन के साथ पहुंचे हैं। सचिन के साथ उनकी बहु सानिया चंदोक, बेटी सारा तेंदुलकर एवं सचिन फाउंडेशन के 5 सदस्य भी पहुंचे हैं। कभी नक्सलवाद की दहशत से पहचान बनाने वाला बस्तर अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। जिस धरती पर कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब खेल और विकास की आवाज बुलंद हो रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन तेंदुलकर ने बताया कि बस्तर में 50 स्कूल मैदानों को विकसित किया जाएगा, जहां बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। सचिन ने बताया, 'मैदान कप' प्रतियोगिता के जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इस पहल को मानदेशी और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। करीब 5 हजार से ज्यादा बच्चों को इस अभियान से सीधा लाभ मिलेगा। कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल जैसे खेलों के जरिए बस्तर के युवाओं को नई पहचान देने की तैयारी है। इस दौरान स्थानीय क्रिकेट प्रेमी बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने सचिन का स्वागत किया। सचिन तेंदुलकर ने बच्चों के बल्ले पर ऑटोग्राफ भी दिया, जिसे पाकर मासूम चेहरों पर खुशी झलक उठी।

सूरजपुर में बाल विवाह पर सख्ती चार महीने में 40 शादियां रोकी गई

■ सूरजपुर में टास्क फोर्स और सूचना तंत्र मजबूत कर टास्क फोर्स के जरिए बाल विवाह रोका जा रहा है

सूरजपुर। बाल विवाह एक अपराध है। लगातार प्रयास और जागरूकता से बाल विवाह में कमी तो आई है, लेकिन अब भी ग्रामीण इलाकों में कम उम्र में लड़कियों की शादी कराई जा रही है। ऐसे में टास्क फोर्स बनाकर बाल विवाह रोके जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी सख्ती बरती जा रही है।

बीते चार माह में 40 बाल विवाह रोके गए हैं। सूरजपुर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि जनवरी 2026 से अबतक 40 बाल विवाह रोके गए हैं। अक्षय तृतीया पर ही बीते तीन-चार दिनों में 13 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्थानीय जिला न्यायालय से सामंजस्य स्थापित कर अब बाल विवाह के मामलों में कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही की जाएगी।

सूरजपुर जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल कहते हैं कि बाल विवाह पर लगातार रोक लगाई जा रही है। इसके लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन में तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन, पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सचिवों को मिलाकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत सूत्रों से भी जानकारी ली जाती है और लगातार बाल विवाह पर रोक लगाई जा रही है। इस दौरान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सभी विकासखंडों में टास्क फोर्स है। अक्षय तृतीय पर सभी ब्लॉक में टीम मौजूद रही। व्यक्तिगत सूचना तंत्र भी विकसित किया गया है।

सूचना मिलने पर तुरंत बाल विवाह रोका जाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जिद की वजह से या पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से लोग बाल विवाह कर रहे हैं। बाल विवाह में अब एफआईआर की प्रक्रिया की जाएगी।

हमने कोर्ट में भी चर्चा की है। अब हम कोर्ट की प्रक्रिया में जा रहे हैं। बाल विवाह मुक्त सूरजपुर के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं- मनोज जायसवाल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सूरजपुर समाजसेविका निशी सोनी कहती हैं कि पहले से तो बाल विवाह कम हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। सूरजपुर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन अजय मरकाम कहते हैं कि कम उम्र में मां बनने से डिलिवरी के दौरान भी समस्या आती है। कभी कभी तो मां की मौत हो जाती है।

वहीं होने वाले बच्चों में कुपोषण और उनके औसत जीवन उम्र में भी कमी आती है। सिविल सर्जन अजय मरकाम ने बताया कि कम उम्र में शादी से बच्चे और मां दोनों को नुकसान होता है।

कम उम्र में बच्चे का लालन पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इससे पूरी पीढ़ी पिछड़ जाती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि बाल विवाह न करें।

31 मई तक संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी 6.25 प्रतिशत की छूट

जगदलपुर। नगर पालिक निगम जगदलपुर ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर पर विशेष छूट की घोषणा की है। निगम प्रशासन ने एकमुश्त भुगतान करने वाले करदाताओं को 6.25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026से 31 मई 2026 तक लागू रहेगी।

निगम आयुक्त प्रवीर वर्मा ने बताया कि नगर निगम निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के तहत लिए गए इस फैसले का उद्देश्य नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। निगम प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल कर संग्रह बढ़ेगा, बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत भी मिलेगी।

जो नागरिक निर्धारित समयावधि के भीतर अपने संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें कुल कर राशि पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को अपने संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान पर ही लागू होगी। यदि कोई करदाता आंशिक भुगतान करता है, तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर पूरा भुगतान कर अधिकतम लाभ लें।

20 फीट ऊंचाई से छलांग लगा रहे युवा

क्या हादसे का इंतजार कर रहा जल संसाधन विभागं

गरियाबंद। जिले के पैरी घूम्मर डैम में इन दिनों गर्मी के चलते सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहां नहाने और घूमने पहुंच रहे हैं। डैम का ठंडा पानी जहां लोगों को राहत दे रहा है, वहीं यहां बढ़ती लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।

डैम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि युवक बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के जान जोखिम में डालकर करीब 20 फीट ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मौके पर न तो चेतावनी बोर्ड लगे हैं और न ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। पानी की गहराई और नीचे मौजूद पत्थरों का अंदाजा न होने के कारण यह स्टंट कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है।

अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़

■ महाराष्ट्र पासिंग कार खराब होने से खुली पोल, तीन थाना क्षेत्र पार कर चुका था तस्कर

महासमुंद। तहसील कार्यालय के सामने खड़ी एक कार से पेट्रोलिंग टीम ने गांजा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह कि ओडिशा से ला रहे गांजा तीन थाना क्षेत्र से गुजर कर महासमुंद मुख्यालय में कार बंद होने पर पकड़ा गया है।

पेट्रोलिंग टीम ने महाराष्ट्र पासिंग कार में सवार दो युवकों से शक के आधार पर पूछताछ की और कार की तलाशी ली तो उसमें गांजा पाया गया। महासमुंद शहर में नेशनल हाईवे 353 स्थित तहसील कार्यालय के सामने मंगलवार की रात करीब 9.15 बजे महाराष्ट्र पासिंग कार एम एच 31 डीसी 2140 बंद हो गई। कार में दो युवक सवार थे। दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन कार चालू नहीं हुआ। युवक डरे सहमे इधर उधर देख रहे थे। इस बीच हाईवे से पेट्रोलिंग वाहन गुजर रही थी। महाराष्ट्र पासिंग होने के कारण पेट्रोलिंग टीम ने कार के करीब जाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोनों युवक घबराते हुए कार बंद पड़ जाने की बात बताई। पेट्रोलिंग टीम ने युवकों से कहां जाना है, इस पर दोनों युवक घबरा गए। टीम को शक हुआ तो दोनों को कार से नीचे उतरने कहा। पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट के नीचे से खाकी टेप से लिपटा हुआ एक-एक किलो गांजा का 15-20 पैकेट निकाला। पेट्रोलिंग टीम ने इसकी सूचना सायबर सेल को दी। सायबर से दो लोग मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को पेट्रोलिंग गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। पेट्रोलिंग टीम आम लोगों की मदद से कार को धक्का देकर सिटी कोतवाली ले गए। पुलिस सहित आम लोग भी जानते हैं कि महासमुंद जिले में पकड़े जाने वाला गांजा ओडिशा से लेकर जिले के रास्ते से होकर गुरता है।

यहां चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र पासिंग कार कोमाखान, बागबाहरा, खल्लारी थाना क्षेत्र से गुजरते हुए महासमुंद शहर में बंद होने से पकड़ा जाता है, जो पुलिस की मुस्तैदी और दावे की कलाई खोल कर रख दी है। बता दें कि करीब दो साल पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था। ओडिशा से गांजा लेकर निकला था और तीन थाना क्षेत्र पार करते हुए खल्लारी थाना पार कर कुछ दूरी पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब घटना की जानकारी लेने कार के पास पुलिस पहुंची तब तक कार छोड़कर सभी फरार हो गए थे। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को गांजा मिला था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ईरान इजराइल वॉर का असर ड्राई होने लगे पेट्रोल पंप

कोरबा। ईरान इजराइल वॉर की परिस्थितियों के बीच जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई किल्लत नहीं है।जबकि मंगलवार शाम को कोरबा शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए। वहीं जिन पंपों में पेट्रोल था वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मंगलवार दोपहर के बाद से ही रिसदी चौक के पास स्थित पुलिस पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो गया। जिसका असर अन्य पेट्रोल पंप पर देखने को मिला। कोसाबाड़ी स्थित एचपी के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लग गई। जहां पेट्रोल लेने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लोग पैनिक होकर खरीदी करने लगे। कोरबा पेट्रोल पंप संचालक संगठन के पदाधिकारी अजय बुधिया ने बताया कि पिछले करीब एक डेढ़ महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के हालात बने हुए हैं। उसकी वजह से ईंधन की आपूर्ति में देश में हर जगह दिक्कत हो रही है। हमारे यहां कोरबा जिले में भी सप्लाई की दिक्कत आ रही है। हम सभी कलेक्टर से इस विषय में मिलने आए थे। पूर्व से ही हम अवगत करा रहे हैं।

प्रभावित मजदूरों को मुआवजा राशि मिलनी शुरु

सक्ती। वेदांता पावर प्लांट हादसा में मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा राशि मिलनी शुरु हो चुकी है. इस हादसे में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है।जबकि 21 मजदूरों के परिजनों को भुगतान दिया जा चुका है।जबकि 3 मजदूरों के परिजनों को भुगतान मिलना शेष है।यही नहीं घायल 11 सभी मजदूरों को मुआवजा राशि मिल चुकी है। अस्पताल में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से 3 की हालत गंभीर है जबकि 6 मजदूर अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं।वहीं कंपनी की ओर से सभी मृतक परिवार को 35-35 लाख और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया है। वहीं सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार दिए जा रहे हैं। आपको बता दें 14 अप्रैल को सक्ती के सिंघीतराई स्थित वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ पावर प्लांट के अंदर बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में प्लांट में काम कर रहे 35 कर्मचारी चपेट में आए थे।

महतारी वंदन योजना हेतु धूप में सीएससी केंद्र पहुंच रहीं महिलाएं

कोरबा। महतारी वंदन योजना के सभी पात्र हितग्राहियों 30 जून 2026 तक ई-केवाईसी हर हाल में करवाना होगा। केवाईसी नहीं होने की स्थिति में योजना के राशि से महिलाएं वंचित हो सकती हैं। आपको बता दें इस योजना से मिलने वाले 1000 रुपए की राशि महिलाओं के लिए बड़ा संबल है। खासतौर पर निचले तबके की जरूरतमंद महिलाएं इस राशि का सदुपयोग कर रही हैं, लेकिन बार-बार की सरकारी प्रक्रिया से वह परेशान भी हैं। चर्चा यह भी है कि बार-बार होने वाली इन प्रक्रियाओ को पूर्ण न कर पाने वाली महिलाओं का नाम कट जाएगा। इसलिए महिलाओं को नियमित अंतरालों पर इस प्रक्रिया से गुजरने की अनिवार्यता लागू की जाती है। ई-केवाईसी का काम जिले के चिन्हांकित सीएससी केंद्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी के माध्यम से नि:शुल्क किया जाएगा। ई-केवाईसी की सुविधा के लिए सभी चॉइस या सीएससी केंद्रों में लैपटॉप एवं बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार महतारी वंदन की राशि जारी तो कर रही है।

कवर्धा में होगी जंगल सफारी 35 किमी सफारी रूट तैयार

कवर्धा। प्रकृति प्रेमियों के लिए सुकूनभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर क्षेत्र में अब भोरमदेव अभयारण्य के तहत जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है। करीब 352 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में भोरमदेव रेंज के अंतर्गत 35 किलोमीटर लंबा सफारी रूट तैयार किया है।इस महीने के अंत में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा इस जंगल सफारी का शुभारंभ करेंगे। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरमदेव मंदिर के समीप करियाआमा क्षेत्र में बनाया गया है, जहां से पर्यटक प्रवेश करेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल 3 सफारी वाहन उपलब्ध हैं, जिनमें एक वाहन में 6 पर्यटक, साथ में ड्राइवर और गाइड यात्रा करेंगे। पर्यटको द्वारा इस रोमांचक सफारी के दौरान पर्यटक घने जंगल, पहाड़, झरने, नदी-नाले और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्सापूर्ण आनंद अपने परिवार के साथ ले सकेंगे।

कन्हर नदी का जलस्तर गिरने से पेयजल सप्लाई प्रभावित

बलरामपुर। रामानुजगंज जिले की जीवनदायिनी कन्हर नदी अप्रैल महीने में सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। इससे नपा क्षेत्र में जल प्रदाय सुविधा और पेयजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके चलते अब नदी में डबरी खुदाई का काम कराया जा रहा है ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए पेयजल की किल्लत न हो। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अप्रैल महीने में ही पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कन्हर नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है। रामानुजगंज शहर की लगभग 25 हजार की आबादी पेयजल और दैनिक जरूरतों के लिए कन्हर नदी पर ही निर्भर है। साथ ही नदी के किनारे बसे गांव और वहां की आबादी भी पेयजल, निस्तारी और खेती सिंचाई के लिए कन्हर नदी पर निर्भर है। कन्हर नदी के पानी को फिल्टर कर इंटकवेल के माध्यम से लोगों के घरों तक सप्लाई किया जाता है। अब नदी का जलस्तर सूखने से पानी सप्लाई मुश्किल हो रही है जिसके चलते नगरपालिका की ओर से जेसीबी के माध्यम से नदी में खुदाई की जा रही है।

बादाम कांडः छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के घर खरीदने वालों के आरोप

■ गृह निर्माण मंडल के ऑफिस पहुंचे व्यक्ति ने बताया कि उनके रिश्तेदार ने हाउसिंग बोर्ड से मकान लिया, जो उनकी जिंदगी का बड़ा पाप था.

बिलासपुर। गृह निर्माण मंडल से जुड़ा चर्चित बादाम कांड सुर्खियों में है। हितग्राही तरूण साहू द्वारा अधिकारी के सामने टेबल पर बादाम का पैकेट खोलकर डालने और उसे खाकर याददाशत तेज करने की सलाह देने का वीडियो देशभर में छाया हुआ है। गृह निर्माण मंडल में चक्कर लगाने वाले सिर्फ अकेले तरुण साहू नहीं है। कई लोग अपने कामों को लेकर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के सालों से चक्कर लगा रहे हैं। तरुण साहू जैसे कई लोग हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के बाहर बैठे हुए मिले। उनमें से कई लोगों ने बताया कि मामूली काम के लिए वे सालों से हाउसिंग बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाकर अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। 75 वर्षीय बुजुर्ग सेवक दास बताते हैं कि देवरीखुर्द में उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से मकान खरीदा था। साल 2023 में रजिस्ट्री के बाद उन्होंने नामांतरण के लिए रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जमा किया लेकिन 3 साल बाद भी उनका नामांतरण नहीं हुआ। बार बार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। नामांतरण के लिये पहुंचे देवरीखुर्द के राजेश पटेल अपने साथ लाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहते हैं 28/05/2024 का यह कागजात है, जिसे हमने नामांतरण कराने विभाग में आवेदन दिया था। उसके बाद फिर 11/05/2025 को नामांतरण के लिए आवेदन दिया। इसपर भी नामांतरण नहीं हुआ तो संपदा अधिकारी को जल्द नामांतरण करने आवेदन दिया। जिस पर वहां से 22/01/26 को हमें 41 हजार 300 जमा करने लेटर आया।, जिसके बाद हमने ऑनलाइन रकम जमा भी कर दिया। पेपर में प्रेषित प्रकाशित होने के बाद भी मेरा नामांतरण अब भी रुका हुआ है। नई मैडम ने आश्वासन दिया है। देवरीखुर्द के मानिकपुरी अपने साढ़ू भाई के साथ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस पहुंचे हैं। वे कहते हैं कि हम जब भी हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस आते हैं तो यही कहा जाता है कि फाइल रायुपर में है, वहां से आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मानिकपुरी ने हाउसिंग बोर्ड में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। वे कहते हैं कि नामांतरण के लिए पैसा भी जमा कराया गया, पैसा गबन करने वाले कर्मचारी और अधिकारी पैसों का भार हितग्राहियों पर डाल रहे हैं और दोबारा भी पैसा मांगा जा रहा है। वे कहते हैं उनके साढ़ू भाई रिटायर होने के बाद भी बार बार ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं।

पुलिस जन मित्र योजना : पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच संवाद

■ विश्वास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने दुर्ग पुलिस की अहम पहल

दुर्ग। पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच संवाद, विश्वास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना सुपेला एवं थाना खुर्सीपार क्षेत्र में पुलिस जन मित्र योजना का शुभारंभ किया।

इस योजना के तहत दुर्ग पुलिस नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, डिजिटल सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, सूने मकानों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर रही है। विभिन्न जन-जागरूकता पोस्टर एवं मार्गदर्शिका के माध्यम से नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर 1930 (साइबर फ्रॉड), 1091 (महिला सुरक्षा) एवं 1033 (नशा नियंत्रण) की जानकारी दी जाकर आवश्यक सुरक्षा उपायों एवं सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है।

यह पहल सामुदायिक पुलिसिंग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से नागरिकों को पुलिस कार्यों से जोड़ते हुए उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता, बेहतर समन्वय एवं अपराधों की रोकथाम में सहायता प्राप्त होगी।

आम नागरिकों से दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पुलिस जन मित्र योजना से जुड़कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा साइबर अपराध, नशा, यातायात नियमों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहें।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देकर सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

संक्षिप्त समाचार

रिहायशी मकान से महाराष्ट्र निर्मित 'संत्री' शराब बरामद

रायपुर। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते बागनदी थाना क्षेत्र के एक रिहायशी मकान से महाराष्ट्र राज्य निर्मित 12.60 लीटर 'संत्री' शराब बरामद की है। आबकारी विभाग की टीम ने अमृत पाल सिंह भाटिया के बागनदी स्थित मकान में दबिश देकर 140 नग, प्रत्येक 90 एमएल की बोतलों में भरी कुल 12.60 बल्क लीटर देशी दारू जब्त की। उक्त शराब बिना वैध अनुमति के संग्रहित की गई थी। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है।

शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन में शामिल एक पोकलेन और 3 हाइवा जब्त

रायपुर। मुंगेली जिले में अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अवैध खनन में संलिप्त एक पोकलेन मशीन और तीन हाइवा वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में मुंगेली विकासखंड के ग्राम अमरटापू (मोतिमपुर) क्षेत्र में बिना अनुमति खनन कार्य संचालित पाया गया। जानकारी के अनुसार मुंगेली एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान शासकीय भूमि पर अवैध रूप से खनिज उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित मशीनरी एवं वाहनों को जब्त कर लिया गया। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर में होने वाली इस परीक्षा में करीब 34 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए व्यापमं ने समय, ड्रेस कोड और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026, रविवार को किया जाएगा। यह परीक्षा रायपुर जिले के 104 केंद्रों में आयोजित होगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में कुल 34,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन और व्यापमं द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो सके। व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9ः30 बजे तक ही दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवारों को कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी या देरी न हो। इससे समय पर केंद्र पहुंचना आसान होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग (जांच) की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापमं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधनों के उपयोग को रोका जा सके।

अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, 4 मई से

रायपुर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रायपुर जिले में बड़ी सुविधा शुरू की गई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा अभ्यर्थियों को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जिले में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 मई 2026 से शुरू होकर 4 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण तैयारी का मौका देना है। अभ्यर्थियों की संख्या और उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को जिला एवं विकासखंड स्तर आयोजित किया जाएगा।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल रंग लाई, दूरस्थ गांवों में बिजली से विकास को गति

रायपुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है, विशेषकर उन दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में जहां वर्षों से बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के वनांचल क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल साकार हुई है, जो आने वाले समय में इन क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली साबित होगी।राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से भटगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों और आश्रित टोलों में विद्युतीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (ष्टस्क्ष्ष्टरु) द्वारा इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और संबंधित कार्यों के लिए औपचारिक कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध

है। इस योजना के तहत कोल्हुआ, महुली, करोटी, चोंगा सहित कई ग्राम पंचायतों के विभिन्न टोलों में पहली बार नियमित बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें स्कूलपारा, हरिजनपारा, पांडोपारा, खासपारा, पहाड़पारा, मधवानीपारा, आमपारा और श्यामपारा जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां अब तक लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर थे। इसके अतिरिक्त कछवारी, खैरा, नवडीहा और कछिया जैसे अन्य क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे व्यापक स्तर पर ग्रामीण आबादी को लाभ मिलने वाला है। विद्युतीकरण के इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सीएसपीडीसीएल द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी कार्यों को प्रारंभ होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सूरजपुर के कार्यपालन अभियंता को परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही या देरी न हो। वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए यह पहल किसी वरदान से कम नहीं है। वर्षों से यहां के लोग बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सीमित रही है। रात के समय अंधेरा होने के कारण सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी बनी रहती थीं। अब जब इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचेगी, तो इन सभी समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इस योजना के लागू होने से न केवल घरेलू जीवन में सुधार आएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजली उपलब्ध होने से छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सिलाई, बढ़ईगिरी, वेल्डिंग और अन्य व्यवसायों को गति मिलेगी, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके अलावा, किसानों को भी सिंचाई के लिए बेहतर साधन उपलब्ध होंगे, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। डिजिटल युग में बिजली की उपलब्धता का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार संभव होगा। इससे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। डिजिटल बैंकिंग और अन्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ने से आर्थिक लेन-देन भी सरल और सुरक्षित होगा। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सोच और दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो रही है और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे और हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो।

हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ और अन्य वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। हाल के नीतिगत बदलावों और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है।

हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। वर्ष 2026 में राज्य के 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। इस वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं। बस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण होने की संभावना है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। बस्तर संभाग में वर्ष 2025 के 3.90 लाख परिवारों की तुलना में इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 4.04 लाख हो गई है। इस साल अब तक 14 हजार 57 नए परिवार इस कार्य से जुड़े हैं।

10 नए फड़ और बेहतर तैयारी

नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में पहली बार 10 नए फड़ों की स्थापना की गई है, जहां 2100 से अधिक मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है। इसके अलावा सुकमा और केशकाल क्षेत्रों मंक भी नए फड़ जोड़े गए हैं। पिछले वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बाधाओं के कारण 351 फड़ों में संग्रहण नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष सभी फड़ों में कार्य शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

सुगम संचालन और पारदर्शी भुगतान

संग्रहण कार्य को सुचारू बनाने के लिए संग्राहक कार्ड, बोरा, सुतली, गोदाम और परिवहन जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

राज्यपाल डेका से नो प्लास्टिक कैंपेन की ब्रांड एंबेसडर श्रीमती आप्टे ने की मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में नो प्लास्टिक अभियान की ब्रांड एंबेसडर श्रीमती शुभांगी आप्टे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने रायपुर नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और जनजागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी। श्रीमती आप्टे ने बताया कि अब तक वे स्कूलों, बैंकों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 55 हजार से अधिक कपड़े की थैलियों का वितरण कर चुकी हैं, ताकि लोगों को प्लास्टिक उपयोग से दूर किया जा सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि में 6 पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया है। साथ ही शासकीय अस्पतालों में जरूरतमंद माताओं और नवजात शिशुओं के लिए जच्चा-बच्चा किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यपाल ने उनके सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।

एक्सिस ट्रस्टी ने डिजिटल ट्रस्टी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया प्रिज्म प्लेटफॉम

रायपुर। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड (एटीएसएल), जो एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और भारत की प्रमुख ट्रस्टी सेवाएं देने वाली कंपनियों में शामिल है, ने प्रिज्म नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के साथ जुड़ाव को बेहतर बनाना और सेवाओं को अधिक सरल और तेज बनाना है। यह लॉन्च एक्सिस ट्रस्टी के फिनटेक आधारित ट्रस्टी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लेटफॉर्म का औपचारिक शुभारंभ एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी और एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ राहुल चौधरी ने किया। यह लॉन्च डिजिटल नवाचार और बदलाव को आगे बढ़ाने के प्रति समूह की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रिज्म का लॉन्च सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (ईओडीबी) पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और बाजार में कामकाज को तेज व अधिक प्रभावी बनाना है। प्रिज्म के माध्यम से एक्सिस ट्रस्टी ग्राहकों से जुड़े प्रमुख कार्यों को डिजिटल बना रहा है और ट्रस्टी सेवाओं की प्रक्रियाओं व अनुपालन को बेहतर कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह उपयोग में आसान, तेज और पारदर्शी अनुभव दे। प्रिज्म महत्वपूर्ण ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर तकनीक को जोड़ता है,

जिससे काम पूरा होने में लगने वाला समय कम होगा, जवाब देने की गति बेहतर होगी और कामकाज की दक्षता व नियमों के पालन में सुधार होगा। लॉन्च के मौके पर एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री राहुल चौधरी ने कहाः प्रिज्म हमारे ट्रस्टी सेवाओं को डिजिटल तरीके से नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसे-जैसे वित्तीय बाजार बदल रहे हैं, ट्रस्टी की भूमिका भी पारंपरिक निगरानी से आगे बढ़कर ग्राहकों के लिए एक अधिक जुड़ा हुआ और जानकारी-आधारित साझेदार बनने की ओर बढ़ रही है। प्रिज्म के माध्यम से हम प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सभी हितधारकों के लिए सेवाओं को अधिक सहज और प्रभावी बनाना चाहते हैं। यह प्लेटफॉर्म ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ हमारी कार्यक्षमता को भी मजबूत करेगा। एक्सिस ट्रस्टी में हम लगातार नई तकनीकों जैसे एआई और उन्नत डेटा विश्लेषण के उपयोग पर काम कर रहे हैं। ताकि जोखिम की बेहतर निगरानी, सही निर्णय लेने और अनुपालन व प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जा सके।

खड़गे के बयान पर सियासत, विधायक अजय चंद्राकर ने कसा तंज, कहा- संन्यास लेकर जपे माला

रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने खड़गे के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों के निकट संपर्क में है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आतंकवादियों के साथ डिनर करते थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज पहली बार भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के दौरे को लेकर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। किसी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे उसका संदेश जाएगा ही। जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं, उसे बहुआयामी बनाए का

सरकार प्रयास कर रही है।

सचिन की सुरक्षा पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

सचिन तेंदुलकर प्रस्तावित दौरे में बदलाव हुआ, गिदम के जांवगा और पनेड़ा के अलावा छिंदनार ही जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आंनद शुक्ला ने सचिन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सवाद खात्मे का दावा करने वाली भाजपा देश के लीजेंड क्रिकेट खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। इसी पर अब भाजपा विधायक चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि कांग्रेस किस आधार पर आरोप लगा रही है। जितना प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर हो उनके लिए ऐसी बाते नहीं कहनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का छवि खराब होता है। कांग्रेस का प्रयास यही है कि छत्तीसगढ़ की छवि खराब हो। विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल, नेता प्रतिपक्ष पर चंद्राकर ने किया हमला छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल्द ही विशेष सत्र की चर्चा है, जिसमें राज्य सरकार निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है। महिला आरक्षण कानून और डीलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित न होने के विरोध में यह प्रस्ताव लाया जाएगा।

एआईएस के बाद अब कांग्रेस नेता फंसे

गार्ड ने किसी तरह निकाला बाहर सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

रायपुर। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर में लिफ्ट से जुड़ी लापरवाही का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। द्वस् ऋचा शर्मा के लिफ्ट में फंसने की घटना के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली भी इसी तरह की स्थिति का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक, नितिन भंसाली बुधवार को करेंसी टावर पहुंचे थे, जहां वे भी कुछ समय के लिए लिफ्ट में फंस गए। इस दौरान लिफ्ट का सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। मदद के लिए कोई व्यवस्था न होने पर उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा पीटना शुरू किया। आवाज सुनकर मौके पर मौजूद गार्ड ने किसी तरह दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाला। इस घटना के बाद पूरे कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, इस बड़े कॉम्प्लेक्स में करीब 850 दुकानें और ऑफिस संचालित हैं,

लेकिन यहां केवल 4 लिफ्ट हैं। उनमें से भी केवल 2 ही किसी तरह संचालित हो रही हैं, जबकि बाकी लिफ्ट बंद पड़ी हैं। जो लिफ्ट चालू हैं, वे भी बार-बार खराब हो जाती हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है।

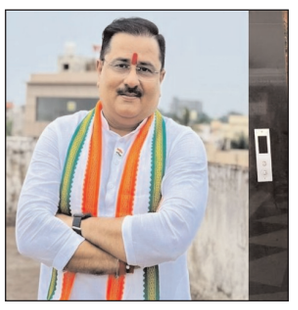

लिफ्ट की सीमित उपलब्धता के कारण लोगों की लंबी कतारें लगती हैं और कई बार काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। स्थिति यह है कि रोजाना अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लिफ्ट के अंदर न तो कोई हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित है और न ही इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है। ऐसे में लिफ्ट फंसने की स्थिति में लोगों को खुद ही किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब करेंसी टावर में लिफ्ट फंसी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। सोमवार सुबह करीब 6ः30 बजे,ष्टस् ऋचा शर्मा करीब 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। उस दौरान लिफ्ट के भीतर न पर्याप्त रोशनी थी और न ही हवा की समुचित व्यवस्था, जिससे उन्हें घबराहट का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया।

वर्मी कंपोस्ट उत्पादन बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल

रायपुर। वर्मी कंपोस्ट (केंचुआ खाद) उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, विशेषकर महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल बन गया है। यह कम लागत वाला व्यवसाय न केवल जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करके मिट्टी की उर्वरता को भी पुनर्स्थापित कर रहा है।

वर्मी कंपोस्ट उत्पादन बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कवर्धा परियोजना मंडल ने नवाचार और बेहतर प्रबंधन से एक नई सफलता की कहानी लिखी है। यहां गुडली रोपणी में वर्मी कंपोस्ट (केंचुआ खाद) का उत्पादन शुरू कर न केवल अपनी जरूरतें पूरी की जा रही हैं, बल्कि अब यह मंडल आय अर्जित करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। गुडली रोपणी में बिना अतिरिक्त बजट लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर

उपयोग कर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन शुरू किया गया। यहां 6 वर्मी टैंकों के माध्यम से केवल 3 माह में 150 क्विंटल खाद तैयार की गई।

इस आधार पर सालभर में लगभग 600 क्विंटल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल यह साबित करती है कि सही योजना और प्रबंधन से सीमित संसाधनों में भी बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

खरीदार से बने विक्रेता

पहले कवर्धा परियोजना मंडल को अपनी नर्सरी के लिए बाहर से खाद खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद भी यहां 500 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है, जिसे अन्य परियोजना मंडलों को बेचा जाएगा। इससे परिवहन और खरीद लागत में बचत होगी और निगम की आय भी बढ़ेगी।

स्थानीय लोगों को मिला रोजगार

इस परियोजना का लाभ केवल विभाग तक सीमित नहीं है। खाद निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ा गया है, जिससे उन्हें गांव के पास ही रोजगार मिल रहा है और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। वन विकास निगम अब इस वर्मी कंपोस्ट को एक ब्रांड के रूप में बाजार में लाने की तैयारी कर रहा है। भविष्य में इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग से न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।कवर्धा परियोजना मंडल की यह पहल अन्य परियोजना मंडलों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। यह उदाहरण दर्शाता है कि सरकारी विभाग भी नवाचार और बेहतर प्रबंधन से आत्मनिर्भर और लाभकारी बन सकते हैं।वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की यह पहल न केवल वन विभाग की सफलता है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जिला-बीजापुर (छ. ग.)

-:: मैनुअल पद्धति जोनल निविदा सूचना प्रथम बार ::-

-: निविदा क्रमांक -02 :-

क्रमांक /330/ निविदा/ग्रा.यां. सेवा/2025-26 बीजापुर, दिनांक 17/04/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित जनपद पंचायत अन्तर्गत आंतरिक विद्युतीकरण कार्यो हेतु मेनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि 30.04.2026 को अपरान्ह 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है, तथा निविदा दिनांक 01.05.2026 को 3.30 बजे अपरान्ह मे खोली जावेगी :-

सक्र	कार्य का नाम	वि0खं0	विद्युतीकरण कार्य के लिये वित्तीय वर्ष के अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
1	जनपद पंचायत बीजापुर / भैरमगढ़ / भोपालपटनम / उसूर अतर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत रू. 10.00 लाख से कम लागत के भवन निर्माण कार्यों में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	बीजापुर	10.00	30/04/2026

निविदा की सामान्य शर्ते, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट-2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://res.cg.gov.in में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.04.2026 को 5.30 बजे सायं से देखी जा सकती है।

जी-262700301/4

कार्यापालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बीजापुर
जिला -बीजापुर (छ.ग.)

महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष का रुख

पूनम आई. कौशिश

पिछला शुक्रवार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहला, मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार को 2014 में सत्ता में आने के बाद पहली बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, वर्ष 2011 के बाद लोकसभा में पहली बार संविधान संशोधन विधेयक गिरा और यह विधेयक अपेक्षित बहुमत के लिए 352 मत नहीं जुटा पाया तथा 54 मतों से गिर गया। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य वर्ष 2029 के चुनावों से पूर्व महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना था। इसका मूल कारण यह था कि इसे परिसीमन विधेयक 2026 से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 2016 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया जाना है। सरकार ने लोकसभा की सीटों को वर्तमान 543 से 850 करने और राज्यों में विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया, किंतु विपक्षी दलों के सरकार के साथ टकराव और विश्वास के अभाव के चलते यह नहीं हो सका। यह विधेयक उस समय लाया गया जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इससे अविश्वास बढ़ा तथा सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत द्वारा किसी समाधान तक पहुंचने की संभावनाएं कम हो गईं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विवादों के समाधान की जो परंपरागत विधियां थीं, वे पूर्णत: धराशायी हो गईं। क्षेत्रीय दल हमेशा राष्ट्रीय सुधारों से अधिक अपने गणित को महत्व देते हैं। तथापि सरकार लोकसभा के जनादेश से बच नहीं सकती और उसे भविष्य के लिए सबक लेना होगा। अपने ही विधेयक को पारित कराने में विफल रहने से सरकार की वह सीमा सामने आ गई कि वह अपने बलबूते पर बदलाव नहीं ला सकती। विशेषकर तब जब संस्थागत निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हों। विपक्ष के लिए यह क्षण इस बात का अहसास करता है कि जब वह एकजुट होता है, एक आवाज में बोलता है और साथ रहता है तो उसे आगे बढने़ से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष ने कहा कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया और सरकार ने अपने 2023 के रुख को बदल दिया तथा सरकार के इस रुख पर प्रश्न उठाया कि महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान में जारी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा जिसमें जाति जनगणना भी हो रही है। इसके साथ ही परिसीमन के संस्थागत तंत्र के बारे में भी अविश्वास व्यक्त किया गया और इस आशंका को बल दिया गया कि प्रतिनिधित्व में समानता और संघीय निष्पक्षता के बीच नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है और राज्य एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। किंतु विपक्ष अपनी इस जीत पर लंबे समय तक हर्षोल्लास नहीं मना पाएगा क्योंकि विधेयक पर सरकार को हराना और राष्ट्रीय नैरेटिव को जीतना दो अलग बातें हैं और उसे ऐसी भाषा अपनानी पड़ेगी जिससे वह न केवल भाजपा के जाल से निकले, अपितु जनता को यह भी समझाए कि उसने इस विधेयक का विरोध क्यों किया और वह इस विधेयक के स्थान पर क्या चाहता है क्योंकि उसका राजनीतिक तथा चुनावी भविष्य इस पर निर्भर है। क्षेत्रीय क्षत्रप, विशेषकर तृणमूल की ममता और द्रमुक के स्टालिन इस समय राज्य विधानसभा चुनावों का सामना कर रहे हैं और उन्हें महिला आरक्षण विधेयक के जाल में नहीं फंसना चाहिए, अपितु अपने राज्यों को सीटों के पुनर्वितरण से होने वाले नुकसान पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि इससे विपक्ष का प्रहार कमजोर हो जाएगा। भाजपा इस ऐतिहासिक सुधार का श्रेय लेती है और अब वह इसको लागू कराने में विफल रही तो वह अगले 3 वर्ष प्रत्येक महिला को यह बताती रहेगी कि हमने उन्हें शक्ति देने का प्रयास किया, किंतु कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया।

बंगाल में ममता को सताने लगा हार का डर

कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

पश्चिम बंगाल चुनाव दिनों-दिन बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। अजेय समझी जाने वाली ममता बनर्जी हैरान, परेशानी और आक्रोशित दिखाई दे रही हैं। हाल ही में एक चुनावी सभा में उनका ये बयान - रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे; खूब चर्चा में है। जहां कुछ सियासी पंडित इसे ममता बनर्जी के चुनाव में सरेंडर करने से जोड़ रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि- ये उनका शक्ति प्रदर्शन का अंदाज़ ए बयां है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी लिहाज़ से ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं हैं।

अपने चुनावी अभियान के बीच ममता बनर्जी उकसावे वाले बयान दे रही हैं।चुनाव कराने आए सुरक्षाबलों के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रही हैं। 25 मार्च 2026 को दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में नंदप्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान में आयोजित एक जनसभा में उनका उकसावे वाला बयान सामने आया। एक वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर सीआरपीएफ के जवानों को 'धमकाती' नजर आ रही हैं। आरोप है कि जनसभा के दौरान उन्होंने सभी महिलाओं और लड़कियों से अपील की कि- वे भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर मौजूद रहें। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि —अगर जरूरत पड़े तो महिलाएं सीआरपीएफ जवानों से 'निपटने' के लिए घरेलू रसोई के उपकरणों (जैसे बर्तन या अन्य सामान) का इस्तेमाल करें।

इस खीझ, उकसावे से — ये आईने की तरह साफ़ हो रहा है कि बंगाल की सियासी पिच से ममता बाहर हो चुकी हैं। इसी के चलते वो किसी भी मुद्दे पर जनता के बीच ख़ुद को साबित नहीं कर पा रही हैं।तिस पर ऐसे बयान दे रही हैं मानो पश्चिम बंगाल — भारत से अलग कोई देश है। जहां ममता बनर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। ममता बनर्जी को लगता है कि वो संविधान से ऊपर हैं।लेकिन ऐसा कतई नहीं है। यहां जनता से बढ़कर कोई नहीं।ममता बनर्जी जिस मुस्लिम वोटबैंक के नाम पर एक छत्र राज कर रही थीं। वो मुस्लिम समुदाय अब अपने %इस्लामी% एजेंडे की ओर बढ़ चला है। हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता — मुस्लिम सत्ता और वर्चस्व की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी की वोटकटवा वाली भूमिका में है। साफ़ है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी के खाते में क्रेडिट होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी,ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ़ बिगुल फूंक रहे हैं। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वर्ग भी भाजपा की रैलियों और जनसभाओं में नज़र आ रहा है। मुस्लिम महिलाएं और पुरुष ये कहते देखे गए हैं कि —ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ममता मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर केवल डराने का काम कर रही हैं। जबकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वहां मुसलमानों में कोई भय नहीं है वहां विकास हो रहा है।

ममता के मुस्लिम तुष्टिकरण से बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर स्थानीय लोग ख़ासे चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल में खुलेआम होती गौहत्याएं, जनसांख्यिकी बदलाव, गुंडागर्दी, हिंसा, अराजकता और अपराधियों को मिलते संरक्षण से वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है।

ये संकेत बता रहे हैं कि वंदेमातरम् की राष्ट्रीय चेतना वाली बंगभूमि जागृत हो चुकी है। वहां का जन-मानस ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाला है। बंगाली भद्रोलोक में इस बार गहन चिंतन मंथन चला है।उनका मानना है कि अगर ममता बनर्जी, अपने मज़हबी तुष्टिकरण, अवैध घुसपैठियों को संरक्षण न देतीं। दुर्गा पूजा, रामनवमी, हिन्दू त्योहारों पर लगातार अंकुश लगाने का प्रयास न करती तो उनके प्रति सहानुभूति बनी रहती।लेकिन ममता बनर्जी ने जिस ढंग से हिंदू समुदाय के ख़िलाफ़ हुई हिंसाओं में मौन साधे रखा। मज़हबी कट्टरपंथियों को संरक्षण देती रहीं। उससे बंगाली समुदाय के स्वाभिमान को धक्का लगा। संदेशखाली, आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुर्गापुर लॉ कॉलेज, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में महिलाओं के साथ हुए दुराचार, अत्याचार की — वीभत्स घटनाओं ने, उनके महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। एक महिला होने के नाते भी ममता बनर्जी का असंवेदनशील रूप पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है। जो ये बताता है कि वो सिर्फ़ अपने वोटबैंक की राजनीति करती हैं। उनके लिए महिला सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है।

वहीं ममता बनर्जी का खुलकर मुस्लिम पक्षकार के तौर पर आना। लगातार केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू न करना। केंद्र से हर मुद्दे पर टकराव लेना। एसआईआर— के विरोध में उतरना। मालदा में ममता राज में, एसआइआर के काम में लगे 3 महिला सहित 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की झकझोर देने वाली घटना ने एक गंभीर ख़तरे की ओर संकेत किया है। जब एक भीड़ ने 9 घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखा। उकसावे के बयान दिए जाते रहे। अधिकारी अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय सुरक्षाबलों ने उन्हें रेस्क्यू किया।

स्थिति की भयावहता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया। देर रात 2बजे तक सुनवाई की और एनआईए को जांच सौंपी। मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि —कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल ने उन्हें देर रात और फिर सुबह इस स्थिति के बारे में सूचित किया था। सूचना मिलने के बावजूद मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और स्थानीय एसपी की भूमिका को बेहद निराशाजनक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि — न्यायाधीशों को डराने-धमकाने या उनके काम में बाधा डालने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्यायपालिका अपने अधिकारियों की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पीठ ने आगे कहा कि राज्य सरकार की निष्क्रियता बेहद निंदनीय है। यह घटना न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और चल रही चुनावी प्रक्रिया को रोकने के लिए सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है।

पहले कम्युनिस्ट शासन उसके बाद ममता बनर्जी सरकार के लंबे समय के अराजक शासन से बंगाल त्रस्त हो गया है। वो अब इन सबसे मुक्ति चाहता है। इसी के दृश्य पश्चिम बंगाल में सर्वत्र दिखाई देते हैं। कोलकाता के रहने वाले एक युवा ने कहा कि— पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाक़ों में अचानक बदलती डेमोग्राफी। पश्चिम बंगाल के संसाधनों पर डाका डालते, बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्याओं से लोगों में भय का वातावरण बना है। लेकिन ममता सरकार में उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये सारी बातें ममता बनर्जी को ख़ासा डैमेज कर रही हैं। सुवेंदु अधिकारी के नामांकन रोड शो, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सभाओं में लगातार उमड़ता विशाल जनसमूह—बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। बीजेपी को लेकर जनता में जैसा उत्साह 2026 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। वो परिवर्तन की बड़ी आहट के तौर पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं, युवा, बुजुर्ग — सभी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केन्द्रीय नेतृत्व, भाजपा की नीतियों को लेकर विश्वास की लहर दौड़ रही है। छोटे-छोटे बच्चे तक अपने माता-पिता के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैलियों में, सभाओं में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र के इंतज़ार में बच्चों के निश्छल, भावुक कर देने वाले वीडियो देखने को मिल रहे हैं। जहां तक नज़र जाती है वहां विशाल जनसमूह दिखाई देता है। जबकि दूसरी ओर ममता बनर्जी की सभाएं खाली दिख रही हैं। इसी के चलते प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने जनसभाओं के आकार को छोटा कर दिया। ममता बनर्जी की सभाओं में लोग उनका बॉयकॉट करते नज़र आ रहे हैं। ये सब स्पष्ट संकेत हैं कि — पश्चिम बंगाल की भूमि इस बार अपने मूल स्वरूप में लौट आई है। संन्यासी क्रांति, वंदेमातरम् की भूमि- हिंसा, अत्याचार, अराजकता से मुक्ति चाहती है। वहीं पश्चिम बंगाल के अतिसंवेदनशील और संवदेनशील इलाक़ों में सेना ने जिस तरह से भयमुक्त निर्वाचन के लिए मोर्चा संभाला है। उससे जनता में उत्साह की लहर देखने को मिली है। लोग भयमुक्त होकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। नए परिवर्तन के लिए आगे आ रहे हैं। स्पष्ट है कि हाल-फिलहाल पूरा गेम ममता के हाथों से फिसलता जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर रुख कर रहा है। ये आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी कि — 4 मई को रिजल्ट के दिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा मैजिक देखने को मिले। टीएमसी दो अंकों में सिमट जाए और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ विजय तिलक करे।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वैदिक स्वरूप

(क) इन्द्र उ वै वातापिः स हि वातमास्वा शरीराण्य-हुँन्प्रतिप्रैति।

(कौषीतकी 27 । 4)

(ख) [इन्द्रः] विश्वरूपं त्वाष्टमभ्यमंस्त, वृत्रमस्तृत यतीन् सालावृकेभ्यः प्रादाद् मरुन्मुखानवधीत्।

(ऐतरेय 7 । 28)

(ग) हेन्द्र उवाच दिवि प्रह्लादीयानतृणमहमन्तरिक्षे पौलोमान्, पृथिव्यां कालकाञ्जांस्तस्य मे तत्र. न लोम च नामीयत, स यो मां [इन्द्रं] वेद नह वै तस्य केनचन कर्मणा लोमो मीयते न स्तेयेन, न भ्रूणहत्यया, न मातृवधेन, न पितृवधेन, नास्य पापं च कृवोमुखान्नीलं वेत्तीति।

(कौषीतकी शं0 नं भाष्य 3 । 1)

(घ) सप्त सप्त हि मरुतां गणः।

(शतपथ 6 । 3 । 125)

(ङ) मरुतोऽब्भिरग्निमतनयन्। तस्य तान्तस्य हृदय-माच्छिन्दन् साऽशनिरभवत्।

(तैत्ति0 1 ।1 ।3 ।3 ।12)

(च) अथैष मरुत्स्तोम एतेन वै मरुतोऽपरिमिती पुष्टिमपुष्यन् ।

(ताण्ड्य 16 । 14 ।1)

(छ) अथैनं [इन्द्रं] ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चांगिरसश्च देवा अभ्यषिचन् ।

(ऐतरेय 8 । 14)

अर्थात् (क) [तब से इन्द्र का नाम वातापि पड़ गया, क्योंकि वह वायु में व्याप्त हो कर शरीर [दिति के पेट में प्रविष्ट हुआ

(ख) इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला, वृत्रासुर का हनन किया, यतियों को सालावृकों के लिये दे डाला, और मरुत् आदि की [गर्भ में काट कर हिंसा की। **क्रमशः ..**

विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस

योगेश कुमार गोयल

पुस्तकों की महत्ता और इनसे अर्जित ज्ञान के संबंध में सदैव कहा जाता रहा है कि ज्ञान कभी बेकार नहीं होता और पुस्तकें विभिन्न संस्कृतियों, पहचानों और भाषाओं के माध्यम से अपनी विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए एक कहानी और एक सामान्य विरासत के आसपास लोगों को एक साथ लाती हैं लेकिन यह चिंताजनक है कि पाठकों में पुस्तकें पढ़ने की आदत निरंतर कम होती जा रही है। लोगों को पुस्तकें पढ़ने, कॉपीराइट कानूनों तथा अन्य उपायों को समझने के लिए प्रोत्साहित करने, लेखकों और पुस्तकों को वैश्विक सम्मान देने तथा पढ़ने की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को यूनेस्को तथा दुनियाभर के अन्य संबंधित संगठनों द्वारा 'विश्व पुस्तक दिवस' मनाया जाता है। 'विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस' का औपचारिक शुभारंभ 'यूनेस्को' द्वारा 23 अप्रैल 1995 को किया गया था।

यह चिंता का विषय है कि आधुनिकता के दौर में बच्चों के साथ-साथ बड़ों का लगाव भी पुस्तकों के प्रति कम हुआ है। मोबाइल और कम्प्यूटर के जमाने में अब बच्चे हों या बड़े, अधिकांश इन्हीं पर अपना ज्यादातर समय बिताने लगे हैं लेकिन अधिकांश विद्वानों का स्पष्ट मत है कि इंटरनेट या विभिन्न संचार माध्यमों से मिलने वाली जानकारियों को हमारे मस्तिष्क को चुपचाप ग्रहण करना पड़ता है, जो दिमाग की खुद की कल्पनाशीलता को कुंद कर देते हैं जबकि पुस्तकें पढ़ने के लिए ध्यान, एकाग्रता और मेहनत की आवश्यकता होती है, जिससे विचारों और भावनाओं के लिए नई रोशनी और प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जरूरी है कि टीवी या सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से चिपके रहने के बजाय पुस्तकों की दुनिया को जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए ताकि रचनात्मकता का उपयोग करते हुए क्षितिज का विस्तार करने में पुस्तकों की शक्ति का बेहतर उपयोग किया जा सके। बाल साहित्य और ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देने और साहित्य के प्रति उनमें आजीवन प्रेम उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जाए। जिस समय हमारे आसपास कोई नहीं होता या हम अकेले अथवा उदास हैं, परेशान हैं, ऐसे समय में पुस्तकें ही हमारी सच्ची दोस्त बनकर हमें सहारा देती हैं। हमारे दिलोदिमाग में उमड़ते सवालों का जवाब पाने के लिए पुस्तकों से बेहतर और कोई जरिया नहीं हो सकता।

सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकों को बढ़ावा देने और पढ़ने की संस्कृति विकसित करने की एक पहल के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली में भव्य पुस्तक मेले 'विश्व पुस्तक मेला' का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन लोगों में किताबें पढ़ने की रूचि विकसित करने के साथ-साथ कलम और मुद्रित दुनिया की ताकत को दोहराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेले के अलावा भी ऐसे क्या प्रयास किए जाएं, जिससे लोगों की दिलचस्पी पुस्तकों के प्रति बढ़े और हिन्दी पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंच सकें? आज के दौर में लोगों की रूचि पुस्तकों में कम होती जा रही है।

भारत व दक्षिण कोरिया के बीच हुई डील के सियासी निहितार्थ

कमलेश पांडे

दुनियाभर में भारत की कूटनीति अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चित रहती आई है, क्योंकि हम तमाम हानि-लाभ की परवाह किए बगैर वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवंतु सुखिनः के सभ्यता-संस्कृतिगत सिद्धांतों को अमलीजामा पहनाते आए हैं। हालांकि कोई इसे गुटनिरपेक्षता समझता है तो कोई निज स्वार्थपरकता, जो गलत भी नहीं है। आखिर बिना स्वार्थ साधे परमार्थ भी किया जाए तो कैसे? इसलिए व्यवहारम फलदायकम हमारा मूलमंत्र है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुई नई डील (व्यापार, तकनीक, रक्षा और ऊर्जा सहयोग) को इसी नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे ही द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ हिंद प्रशांत के रणनीतिक संतुलन में भी गहरे सियासी निहितार्थ निकलते हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से इसे समझते हैं-

पहला, भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति मजबूत होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। जहां भारत दक्षिण कोरिया की विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के घोषणाओं से भारत को उत्तर पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक में एक अलग मध्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। वहीं, दक्षिण कोरिया का भारत नेतृत्व वाली पहलों जैसे इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और सोलर एलायंस में शामिल होना भारत की मल्टी एलायंस रणनीति को वैधता देता है।

दूसरा, अमेरिकी चीन टकराव में एक मजबूत तीसरा धुरा, जो संतुलन कारी साबित हो सकता है। दक्षिण कोरिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अमेरिका का मजबूत सहयोगी है, अब भारत के साथ चिप, एआई, ऊर्जा और जल मार्ग जैसे क्षेत्रों में गहरा तकनीकी आर्थिक सहयोग बना रहा है; यह चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला से बचने के लिए डी-रिस्किंग रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे भारत, अमेरिका जैसे देशों के लिए चीन के बिना एक वैकल्पिक टेक और विनिर्माण हब बनने की दिशा में आगे बढ़ता है,

जिससे हिंद प्रशांत में चीन विरोधी छोटे गुटों के लिए भारत का भू रणनीतिक मूल्य बढ़ता है। भारत इसे भुनाने में भी पीछे नहीं रहता, ताकि भारत के पड़ोसियों से चीन के बेहतर होते सम्बन्धों को उसके पड़ोस से साधकर अपना हित वर्द्धन किया जा सके।

तीसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर इसलिए कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के साथ ही चिप से शिप जैसी डील्स को रफ्तार देने से दोनों देश आपूर्ति श्रृंखलाओं में आपसी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे किसी भी एक बड़े खिलाड़ी (जैसे चीन या अमेरिका) के दबाव से निकलने की लचीलापन बढ़ता है। इसके अलावा, दोनों देशों ने ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक सुरक्षा वार्ता और नौसैनिक लॉजिस्टिक सहयोग पर भी जोर दिया है, जिससे दक्षिण कोरिया को भी भारत के माध्यम से ईरान और मध्य पूर्व से ऊर्जा तक पहुंच के विकल्प मिलते हैं। इससे भारत को विभिन्न तरह की मजबूती मिलती है।

चौथा, चीन और उत्तर कोरिया पर निर्देशित संदेश का रणनीतिक फायदा मिलता है। भारत दक्षिण कोरिया की बढ़ती रक्षा और तकनीकी साझेदारी, खासकर चिप, एआई, डिफेंस इंडस्ट्री और नौसैनिक लॉजिस्टिक पर काम, क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर चीन की समुद्री दबाव रणनीति के खिलाफ एक छोटा बफर बनाती है। यह उत्तर कोरिया के लिए भी यह ज्यादा टेंशन वाला है, क्योंकि दक्षिण कोरिया भारत सहयोग से उसके अपने देश के खिलाफ एक और बाहरी प्रतिनिधित्व बनता है, जो चीन? रूस के साथ उसके एकमात्र बड़े सहयोग पर भी राजनीतिक दबाव डाल सकता है।

पांचवां, भारत के भीतरी राजनीतिक लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के लिए यह डील एक ऐसा नारा बनती है जिससे सत्ताधारी गठबंधन यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि मल्टी एलायंस विदेश नीति और तकनीक आधारित वैश्विक फैक्टरी की तस्वीर धीरे धीरे असली हो रही है। इससे चुनावी राजनीति में मजबूत वैश्विक भागीदार बनने की चित्रण रणनीति मजबूत होती है, खासकर जब भारत अमेरिका, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग गैर आधिकारिक गुटों में एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। चूंकि इससे भारतीय प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, इसलिए सराहनीय पहल है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 15 समझौतों में सीधे तौर पर चिप (सेमीकंडक्टर/एआई टेक) और शिप/पोत (जहाज निर्माण, नौवहन, स्टील, बंदरगाह) से जुड़े कुछ मुख्य सहमति पत्रक (MoUs) इस प्रकार हैं-

पहला, चिप (सेमीकंडक्टर/एआई/टेक) से जुड़े समझौते- एआई, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समझौते : भारत दक्षिण कोरिया के बीच एआई, सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कई सहमति पत्रक (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें साझा शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टार्टअप/कंपनी स्तरीय सहयोग जैसे बिंदु शामिल हैं।

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग (आर्थिक सुरक्षा वार्ता): भारत कोरिया आर्थिक सुरक्षा वार्ता थीम के तहत चिप आधारित क्रिटिकल टेक (सेमीकंडक्टर, एक्ज़ीक्यूटिव ग्रेड टेक) की आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के रूप भी शामिल हैं।

दूसरा, शिप/जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र से जुड़े समझौते- समाचारों में 15 समझौतों की लिस्ट के तौर पर निम्न बिंदु विशेष रूप से पोत निर्माण और समुद्री विकास सहयोग से सीधे जुड़े हैं-

पोत निर्माण (Shipbuilding): भारत दक्षिण कोरिया के बीच जहाज निर्माण और जहाज हार्डवेयर डिज़ाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एक या अधिक सहमति पत्रक (रूपरेखा) हुए, जिनका उद्देश्य भारत के डॉकयार्ड्स और प्राइवेट शिपबिल्डर्स को कोरिया की उन्नत जहाज निर्माण तकनीक से जोड़ना है।

स्टील/इस्पात आपूर्ति श्रंखला के लिए तकनीक और व्यापार: इस्पात उत्पादन और आपूर्ति श्रंखला (जो शिपबिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है) पर तकनीक आधारित सहमति पत्रक (रूप) शामिल, जिससे भारतीय स्टील मिलों और कोरियाई शिपबिल्डर्स के बीच सीधा बंधन बढ़ेगा।

समुद्री विरासत समझौता (Maritime Heritage MoU) : भारत कोरिया के बीच समुद्री इतिहास और संस्कृति संरक्षण, म्यूजियम सहयोग और अंडरवाटर आर्कियोलॉजी जैसे प्रोजेक्टों पर सहमति पत्रक (रूप) हुआ, जो राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर पर समुद्र केंद्रित विज़न को बढ़ावा देता है।

पोर्ट्स क्षेत्र में सहयोग: भारत और दक्षिण कोरिया ने पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण और पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक्स पर अलग सहमति पत्रक (Mo) शामिल किया है, जो चिप से शिप नारे के तहत लॉजिस्टिक्स डिजिटल हार्डवेयर चेन को जोड़ता है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 15 समझौतों में चिप और शिप के अलावा कई अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं- पहला, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक सुरक्षा वार्ता पर एक सहमति पत्रक (Mo): दोनों देश लिक्विड नेचुरल गैस (LNG), रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल टेक आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत कोरिया ऊर्जा आपूर्ति सहमति पत्रक (Mo) ने ऊर्जा आपूर्ति विविधता और आर्थिक राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

आज का इतिहास

1906 रूस के प्रथम राज्य ड्यूमा में मौलिक कानून की घोषणा की गयी।
1908 डेनमार्क, जर्मनी,ब्रिटेन, फ्रांस, हालैंड और स्वीडन के बीच उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि पर हस्ताक्षर किये गये।
1918 प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश रॉयल नेवी ने ब्रूग्स-ज़ेब्रूज के बेल्जियम बंदरगाह पर छापा मारा।
1919 एस्टोनियाई संविधान सभा ने अपना पहला सत्र की शुरुआत की।
1942 दूसरे विश्व युद्ध में कई हफ्ते पहले लुबेक के रॉयल एयर फोर्सबॉम्बिंग के लिए जवाबी कार्रवाई में, लूफ़्टवाफे ने इंग्लैंड में एक्सबॉम्बिंग छापे की एक श्रृंखला शुरू की, एक्सेटर से शुरू किया।
1951 अमेरिकी पत्रकार विलियम एन. ओटिस को चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया था।
1954 सेंट लुइस कार्डिनल्स के विक रासची के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए मिल्वौकी ब्रेव्स के हांकराओन ने मेजर लीग बेसबॉल में अपने तत्कालीन रिकॉर्ड 755 होमरून में से पहला झटका दिया।
1961 अल्जीरियाई युद्ध के बीच में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डीगॉले ने एक सैन्य भाषण दिया, जो सैन्य कर्मियों और स्थानीय लोगों को उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश का विरोध करने के लिए बुला रहा था।
1967 सोयुज 1, सोवियत सोयुज अंतरिक्ष यान का पहला मिशन, बैकोनूर कॉसमोड्रोम से कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था।
1968 कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क शहर में वियतनाम युद्ध का विरोध कर रहे छात्रों ने प्रशासन की इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया और इस विविधता को बंद कर दिया।
1991 ब्योर्न बोर्ग ने 8 साल के अंतराल के बाद जोर्डी एरेसे को 6-2, 6-3 से हराया।
1992 मैकडॉनल्ड्स चीन में अपना पहला फास्ट-फूड रेस्तरां खोलता है।
1996 सोथेबीं ने जैकी ऑस्मियम के 4 दिनों की शुरुआत की, जिसमें 24 मिलियन हिट हुए।
2000 बहमिन की खाड़ी में वायुसेना की उड़ान 72 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 124 लोगों की मौत।
2007 रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइएविच ऐल्तसिन का निधन।

महिला आरक्षण बनेगा भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा!

विनोद अग्निहोत्री

लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा लाया गया संशोधन विधेयक आवश्यक संख्या बल न जुटा पाने की वजह से गिर गया. इसे जहां कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में पहली बार संसद में अपनी जीत के रूप में देख रहा है, वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अभी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों ही पक्ष महिला आरक्षण की तलवार लेकर एक दूसरे के सामने डट गए हैं। इस मुद्दे पर उनके बीच होने वाली तकरार से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होगी। क्या महिलाओं के राजनीतिक आर्थिक सशक्तीकरण को बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से पहले नया जनादेश मांगने जनता के बीच जा सकते हैं?

विधेयक गिरने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दिए गए अपने पूरे भाषण में इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इस कदम को देश की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के खिलाफ बताते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने महिला आरक्षण की भ्रूण हत्या कर दी। जवाब में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार को चुनौती दी कि यदि वह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के प्रति जरा भी गंभीर है तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए तत्काली आरक्षित करने का विधेयक लेकर आए, पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा। सरकार और विपक्ष के इन तेवरों से साफ है कि देश की राजनीति में अब प्रमुख मुद्दा महिला आरक्षण ही होगा। जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने-अपने तरीके से जनता के बीच ले जाएंगे। अब देखना है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं किसके माथे पर अपने समर्थन का तिलक लगाकर उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाती हैं।

सवाल है कि जो मोदी सरकार अपना हर कदम फूंक-फूंक कर नफा-नुकसान का हिसाब लगाकर उठाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारी रणनीति तय करते हैं और उसे अंजाम देते हैं. पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान लोकसभा के बजट सत्र को बढ़ाकर तीन दिन की विशेष बैठक बुलाकर उसमें इतनी हड़बड़ी में महिला आरक्षण कानून 2023 में संविधान संशोधन लाने, 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर नया परिसीमन करके लोकसभा की सीटें 850 तक करके उसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षित

करने का विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ गई. वह भी तब जब सरकार अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास संसद के दोनों सदनों में सांविधानिक संशोधन मंजूर कराने के लिए आवश्यक दो तिहाई सदस्य नहीं हैं। फिर लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान जिस तरह पूरा विपक्ष एकजुट दिखा उससे यह साफ हो गया था कि संविधान संशोधन का मंजूर होना मुमकिन नहीं है। तब सरकार अपनी फजीहत से बचने के लिए विधेयकों को किसी संसदीय समिति को भेजकर कुछ समय के लिए टाल सकती थी। लेकिन उसने ऐसा न करके मत विभाजन का रास्ता क्यों अख्तियार किया? क्यों गुजरात से लेकर केंद्र तक अपने 25 साल के संसदीय और विधायी जीवन में कभी पराजय का मुंह न देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा होने दिया। इसके पीछे आखिर उनकी क्या रणनीति है। क्या ये कदम सिर्फ प.बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों भाजपा को राजनीतिक फायदा देने के लिए उठाया गया और अब भाजपा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के मुद्दे को लेकर इन चुनावों में महिलाओं के वोट पाने की उम्मीद कर रही है या फिर उनकी रणनीति इससे भी बड़े किसी राजनीतिक लाभ पाने के लिए है। ये सारे सवाल सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं और हर कोई अपने-अपने हिसाब से इनके जवाब तलाश रहा है और दे रहा है।

अपनी हार को जीत में और अपने ऊपर होने वाले हमलों को अपना हथियार बनाने की राजनीतिक कला में माहिर रहे नरेंद्र मोदी गुजरात के दिनों से ही बाहर भीतर के विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ते रहे हैं। इसलिए ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है कि उन्हें कैसे महिला आरक्षण के नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संशोधन विधेयक के राजनीतिक भविष्य का अंदाज नहीं रहा होगा। ज्यादातर की राय यही है कि सरकार के इस कदम के पीछे मोदी की कोई बड़ी दीर्घकालिक रणनीति है। जबकि विपक्षी नेताओं का मानना है कि सरकार का अति आत्मविश्वास अब सत्ता के अहंकार में बदल चुका है इसलिए मोदी सरकार को लगता था कि वह महिला आरक्षण की गुलाबी पैकिंग के भीतर सीटों के परिसीमन का विधेयक लेकर आएगी तो विपक्ष संसद में विरोध नहीं कर पाएगा और सरकार अपनी सुविधा और सियासी गणित के मुताबिक लोकसभा की सीटों के ढांचे को मनमाने तरीके से बदलकर भविष्य में अपनी जीत की गारंटी सुनिश्चित कर लेगी। लेकिन विपक्ष इस चाल को भांप गया और उसने महिला आरक्षण के बजाय सीटों के परिसीमन को मुद्दा बनाकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके विधेयक सदन में गिरा दिया।

अब जहां भाजपा इसे महिला आरक्षण की राह में बाधा का मुद्दा बनाकर विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में जुट गई है तो कांग्रेस और अन्य सभी विपक्षी दल परिसीमन की योजना को संघवाद संविधान और लोकतंत्र विरोधी बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ने एक स्वर से मांग की है कि सरकार 2023 में सर्वसम्मति से पारित महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को तत्काल लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में लागू करके एक तिहाई 181 सीटें तत्काल महिलाओं के लिए आरक्षित करे, विपक्ष पूरा साथ देगा। लेकिन सरकार इस पर विपक्ष के साथ कोई संवाद करने और महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए कोई रास्ता निकालने की बजाय संसद में संशोधन विधेयक गिरने को मुद्दा बनाकर जनता के बीच विपक्ष को खलनायक बनाकर महिलाओं के एकमुश्त वोटों की फसल काटना चाहती है।

कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो जरूरी नहीं है कि 2029 तक इंतजार किया जाए सरकार अगले साल 2027 के मार्च अप्रैल जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव होने हैं, उनके साथ ही लोकसभा के मध्यावधि चुनाव का दांव भी खेल सकती है। अब विपक्ष इस रणनीति की काट कैसे करेगा ये बड़ा सवाल है।

सरकार के इस दांव की संभावना से इनकार न करने वाले एक भाजपा नेता का कहना है कि जिस तरह पहले मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण ने राज्य सरकारों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को खत्म करके इन राज्यों में भारी बहुमत से भाजपा और एनडीए की सरकारों की वापसी संभव कराई तो यही प्रयोग देश में क्यों नहीं सफल हो सकता।

भारत को गोली का सही जबाब देना चाहिए

संजय गोस्वामी

शनिवार 18 अप्रैल 26 को होरमुज़ जलडमरूमध्य में भारत के झंडे वाले दो जहाजों पर हुई फायरिंग ने ईरान की सत्ता संरचना में बढ़ती दरार को उजागर कर दिया है। यह फायरिंग इस बात को लेकर हुई भ्रम के कारण हुई कि शनिवार को होरमुज़ जलडमरूमध्य खुला था या नहीं। जहाँ एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि सभी जहाज होरमुज़ जलडमरूमध्य से गुज़र सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ समन्वय करें, वहीं इसके विदेश मंत्री, अब्बास अराघची ने कहा कि फ़ारस की खाड़ी में यह संकरा रास्ता खुला है, क्योंकि लेबनान में इज़राइल-हिज़्बुल्ला युद्ध के लिए संघर्ष-विराम समझौते पर सहमति बन गई थी।

भारत को नेवी शिप भेज कर इसका करारा ज़बाब देना चाहिए भारत 140 करोड़ लोगों का एक लोकतान्त्रिक देश है और भारत ऐसा देश है जो गोली का ज़बाब गोली से देना जानता है भारत के लोग कहीं भी हो अगर हमला हुआ है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए ईरान में सत्ता संघर्ष हो या कुछ भी ऐ एक आतंकवादी घटना है शिप पर भारत का तिरंगा होगा यदि इसे शक्ति से नहीं लिया गया तो आतंकी का हौसला बढ़ेगा और दुनिया में इसे मज़ाक बनाया जाएगा जिससे भारत की छवि धूमिल होगी जब ईरान की नेवी को अमेरिका के हमले से बचाने के लिए कोच्ची में अपना नेवी शिप भेज कर अमेरिका को अपनी ताकत का अहसास करा सकता है तो ऐसा हमला बर्दास्त नहीं है चाहे कोई भी हो भारत को इसका करारा ज़बाब देना चाहिए हम भगवान राम के मार्गदर्शन पर चलने वाले मान और मर्यादा से रहने वाला शांति प्रिय देश है तो हमें अपने लोगों की रक्षा का पूर्ण अधिकार है भारत को इसे गंभीरता से लेकर जबाबी कार्यवाही करना चाहिए अमेरिका क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ऐ दो देशों का अंदरूनी मामला है इसमें भारत का कोई रोल नहीं है भारत एक शान्तिप्रिय देश है और भारत माँ की रक्षा के लिए मर मिटने वाला देश है ऐ हमला बिल्कुल जायज नहीं है इसपर भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए ईरान की आबादी 9 करोड़ है और भारत की आबादी 140 करोड़ है इसे यदि हल्के में लिया गया तो परोसी दुश्मन मुल्क मज़ाक उड़ा सकता है क्योंकि उसके जहाज आ रहे हैँ हम अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर हैं आतंकी हमला बर्दास्त नहीं है.भारत परमाणु संपन्न देश है और भारतीयों की रक्षा के लिए भारतीय सेना पूरे विश्व में अव्वल है भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबन्धन के अधीन हैं। 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की शक्ति के साथ, यह विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है इसलिए भारत को इसका कड़ा जबाब देना चाहिए नहीं तो पाकिस्तान और ईरान दोनों की सीमा सटती है वहाँ से तो आतंकवाद होता रहता है अब यदि धर्म के नाम पर ईरान भी इसी रास्ते चला तो आने वाले समय में आतंकवादी घटना बढ़ेगी लेकिन यहाँ तो एक नारी शक्ति बिल पर राजनीति हो रही जो संसद में पास नहीं हुआ लोकतंत्र है ऐसा होता है इसका सम्मान करना चाहिए हालांकि मुझे भी दु:ख है लेकिन अदालत तो संसद के निर्णय को ही सही मानेगी अगर गलत है तो अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत दे देना लेकिन राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए जाएं वो सही हो इसलिए इस मुद्दे पर कार्यवाही करना चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी : उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

अमिताभ श्रीवास्तव

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में महत्वाकांक्षा रखना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 25 मई 1999 को पार्टी का गठन ही निजी लक्ष्यों पर केंद्रित होकर किया गया था। तब पार्टी के मुखिया शरद पवार कांग्रेस से दूसरी/तीसरी बार अलग हुए थे और इस बार उन्होंने देश के दो अन्य नेताओं पीए संगमा और तारिक अनवर को साथ लिया था। उनके साथ भी महाराष्ट्र कांग्रेस से जितने नेता आए वे सभी निजी सोच और चिंता के साथ गए। पवार सहित सभी नेता कांग्रेस में उतने भी हताश-निराश नहीं थे, जिस तेजी के साथ वे नए दल के साथ हो लिए।

एक बार फिर 24 साल बाद मई 2023 में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ा और उत्तराधिकारी चुनने तक बात पहुंची। लेकिन उस आग को अचानक और बिना कोई कारण बताए बुझा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2023 में पार्टी में विभाजन हो ही गया और 40 विधायकों के साथ एक नया दल अस्तित्व में आ गया।

एक समय जब कांग्रेस से अलग होकर अलग पहचान के लिए प्रयास हुआ, वहीं दूसरी बार नए चेहरे को सामने लाने में बात इतनी उलझ गई कि पार्टी दो-फाड़ हो गई। किंतु आज नेतृत्व का सवाल वही है, जो दो साल पहले उठा था। वह अब विभाजन के बाद एकीकरण के नाम पर अधिक जटिल हो चला है। वर्ष 1999 में जब शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए थे, तब उन्होंने कांग्रेस में विदेशी नेतृत्व का मुद्दा उठाया था,

जिस पर उन्हें व्यापक सहमति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने राज्य के राजनीतिक समीकरण अवश्य ही बदल दिए। अलग होने से पहले और केंद्र में जाने के बाद उन्हें राज्य में अपने किसी नेता को उपमुख्यमंत्री बनाने में सफलता नहीं मिलती, लेकिन नया दल बनाने के बाद उनकी मोलभाव की क्षमता बढ़ी। उन्हें केवल राज्य में उपमुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि अनेक अच्छे विभागों के मंत्री पद मिले।

यही नहीं, केंद्र में भी राजनीतिक हैसियत बढ़ने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अच्छे विभाग हासिल हुए। हालांकि उस समय कांग्रेस से अलग हुए अधिक दिन नहीं बीते थे। दूसरे शब्दों में, थोड़ा-सा खतरा मोल लेकर महत्वाकांक्षा पूरी हो गई थी। उस समय अजित पवार तो उनके परिवार के ही सदस्य थे, लेकिन छगन भुजबल, जयंत पाटिल, मधुकरराव पिचड़, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड़ जैसे अनेक नेता राजनीति में अपना कद रखने के बावजूद शरद पवार की राकांपा की ओर खिंचे चले गए और अधिकतर नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का अवसर मिला। यह राजनीतिक सुख तभी तक बना रहा, जब तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, लेकिन वर्ष 2014 से देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव आने से छिपी असहजता सामने आने लगी। जिसे मूर्त रूप वर्ष 2019 में मिला और आखिरकार राकांपा के समर्थन से राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी। वैसे तो राकांपा में महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमेशा ही कोई न कोई रास्ता निकाला जाता रहा, लेकिन उत्तराधिकार को लेकर कभी स्थितियां साफ नहीं हुईं। राजनीति में शरद पवार के साथ उनके सबसे निकट भतीजे अजित पवार ही रहे। जिन्होंने वर्ष 1991 से वर्ष 2023 तक उन्हें हर प्रकार का साथ दिया। वर्ष 2006 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का राज्यसभा से राजनीति में आगमन हुआ, जिन्होंने सात साल पहले बनी राकांपा पर अजित पवार के वर्चस्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया।

जब सुले वर्ष 2009 में बारामती से लोकसभा के लिए चुनी गईं, तब कई सवालों के जवाब मिलने आरंभ हो गए। उनकी वर्ष 2019 में उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने में भूमिका के बाद कुछ और बातें भी साफ हो गईं। इसीलिए जब दो मई 2023 को शरद पवार ने पार्टी प्रमुख के पद से त्यागपत्र दिया तो उनके उत्तराधिकारी को लेकर जिज्ञासा अधिक बढ़ गई। महत्वाकांक्षी नेताओं के दल में अनेक नेताओं के नाम सामने आने लगे। यद्यपि सभी को मालूम था कि इस घटनाक्रम को सुले या अजित पवार के नाम के बाद विराम मिलेगा। किंतु अंत चौंकाने वाला ही था, जिसमें शरद पवार ने ही इस्तीफा वापस ले लिया। यह तात्कालिक स्तर पर उचित निर्णय कहा गया, मगर इसके दूरगामी परिणामों का आकलन नहीं किया गया। कहीं न कहीं आग बुझाकर एक चिंगारी को छोड़ दिया गया। लिहाजा दो माह बाद पार्टी दो-फाड़ हो गई। वर्ष 2023 में विभाजन के बाद राकांपा का अजित पवार गुट बना। उसने राज्य में भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार के साथ हिस्सेदारी हासिल की। वर्ष 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों ने राकांपा के दोनों गुटों को उनकी ताकत का अनुभव कराया, जिससे नुकसान और फायदे भी सामने आए। यही कुछ बात आपस में विलय की हुई, लेकिन संकट उत्तराधिकारी के नाम पर तैयार हुआ। दुर्भाग्य से इसी बीच अजित पवार असामयिक मौत के शिकार हो गए। परंतु उनके न रहने के बाद कुछ पीछे की पंक्ति में बैठे नेता भी सामने आ गए। जिनमें से एक रोहित पवार भी हैं, जो दूसरी बार विधायक बने। जिनके लिए मंच से अजित पवार कहते थे कि वह उनकी 'कृपा' से विधायक बने। मगर नए माहौल में उनकी तमन्ना छिपाए नहीं छिप रही है। सवाल यही है कि 27 साल पहले महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए गठित पार्टी कब और कैसे अपने नेताओं को संयम और त्याग का पाठ पढ़ाएगी?

ईरान से सटे समंदर की खामोश नाकेबंदी

जाहिद खान

खाड़ी में रोका गया जहाज सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है बल्कि उस बदलती दुनिया की झलक है जहां जंग अब सीधे टकराव से पहले रास्तों पर लड़ी जा रही है। नाम, कंपनी, पाबंदियों का इतिहास और सप्लाई के तरीके जोड़कर देखें तो यह मामला कहीं बड़ा और गहरा नजर आता है।

खाड़ी के पानी में हाल ही में जिस ईरानी कारोबारी जहाज को अमेरिकी नाकेबंदी ने ओमान के पानी पर रोका, उसे लेकर सामने आई जानकारी में उसका नाम एमवी टूस्का बताया गया है। कागजों में यह एक सामान्य कंटेनर जहाज है, जैसा रोज दुनिया भर में हजारों चलते हैं, लेकिन इस बार मामला सीधा नहीं था। समुद्री ट्रैकिंग डेटा और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज चीन के एक औद्योगिक बंदरगाह से निकला, फिर मलेशिया के एक ट्रांजिट पोर्ट पर रुका, जहां कंटेनरों की अदला-बदली हुई और उसके बाद यह ईरान की दिशा में बढ़ रहा था। यह सीधी सप्लाई नहीं थी बल्कि एक ऐसा रास्ता था जिसे जानबूझकर टुकड़ों में बांटा गया था ताकि असली स्रोत और असली गंतव्य को छुपाया जा सके।

जहाज की मालिकाना जानकारी भी सीधी और साफ नहीं मिलती, जो अपने आप में इस पूरे मामले की प्रकृति को समझाती है। ऐसे मामलों में अक्सर शेल यानि जाली कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां कागजों पर एक नाम होता है, संचालन किसी और के हाथ में होता है और असली फायदा किसी तीसरे पक्ष तक जाता है। अमेरिका लंबे समय से इसी तरह के नेटवर्क पर नजर रखता आया है क्योंकि उसका मानना है कि ईरान तक पहुंचने वाली कई सप्लाई इसी तरह के घुमावदार रास्तों से गुजरती हैं। यही वजह है कि इस बार भी कार्रवाई सिर्फ एक जहाज पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर केंद्रित नजर आती है जिससे यह जुड़ा हुआ था।

अमेरिका ने इस जहाज को ओमान की खाड़ी में रोका और कब्जे में लिया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इसमें ड्यूल यूज कैटेगरी का सामान था। यह शब्द सुनने में भले तकनीकी लगे लेकिन इसकी अहमियत बहुत गहरी है। ड्यूल यूज का मतलब है ऐसा सामान जो सामान्य उद्योग में भी काम आता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य उपयोग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें खास तरह की धातु, मजबूत पाइपिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और औद्योगिक मशीनरी जैसी चीजें शामिल होती हैं। यही वे चीजें हैं जो किसी फैक्ट्री में भी लग सकती हैं और यही वे

चीजें हैं जो आगे चलकर मिसाइल या सैन्य ढांचे की रीढ़ बन सकती हैं।

इस कार्रवाई को समझने के लिए पीछे जाना जरूरी है क्योंकि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं है। वर्ष 2018 में जब अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग किया, उसी समय से पाबंदियों का एक नया और ज्यादा सख्त दौर शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका के वित्त विभाग की एजेंसी ओएफएसी ने कई ईरानी कंपनियों, शिपिंग नेटवर्क और उनसे जुड़े बिचौलियों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू किया। इन पाबंदियों का उद्देश्य सिर्फ हथियारों की सप्लाई रोकना नहीं था बल्कि उन सभी रास्तों को सीमित करना था जिनसे ईरान अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमता को मजबूत कर सकता था।

यहीं से इस पूरी घटना का असली अर्थ सामने आता है। यह जहाज इसलिए नहीं रोका गया कि उसमें सीधे हथियार मिले थे बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि यह उस सप्लाई लाइन का हिस्सा माना गया जिसे अमेरिका लंबे समय से कमजोर करना चाहता है। जब किसी देश की सप्लाई लाइन को निशाना बनाया जाता है तो असल में उसके भविष्य की ताकत को निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहती बल्कि एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में देखी जाती है।

ईरान की प्रतिक्रिया को इसी नजरिए से समझना चाहिए। ईरान ने इस कार्रवाई को सीधे समुद्री डकैती कहा और इसका विरोध तीखे शब्दों में किया। यह प्रतिक्रिया सिर्फ भावनात्मक नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी था। ईरान को यह खतरा साफ नजर आ रहा है कि अगर आज एक जहाज रोका गया और उसने कोई मजबूत जवाब नहीं दिया तो कल हर जहाज शक के दायरे में आ सकता है। धीरे-धीरे यह स्थिति ऐसी बन सकती है जहां उसके लिए जरूरी सामान लाना भी मुश्किल हो जाए और यही स्थिति किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है।

इस पूरी घटना की दूसरी परत आर्थिक है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब किसी क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसका असर सिर्फ उस एक जहाज तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समुद्री व्यापार पर पड़ता है। सबसे पहले बीमा कंपनियां उस इलाके को जोखिम वाला घोषित करती हैं जिससे जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है। इसके बाद शिपिंग कंपनियां उस रास्ते से बचने की कोशिश करती हैं और अगर जाती भी हैं तो ज्यादा कीमत वसूलती हैं। धीरे-धीरे वही रास्ता जो पहले सामान्य था, महंगा और असुरक्षित हो जाता है। इस तरह बिना किसी खुले एलान के एक तरह की नाकेबंदी शुरू हो जाती है।

तीसरी परत इस घटना को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है और वह है इसका अंतरराष्ट्रीय आयाम। यह जहाज चीन से चला था, जिसका मतलब यह है कि यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का मामला नहीं है। चीन लंबे समय से ईरान के साथ व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग बनाए हुए है और ऐसे कई रास्ते हैं जिनके जरिए यह सहयोग चलता है। अगर इन रास्तों पर इस तरह की रोक लगती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता बल्कि उन सभी देशों तक जाता है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में चीन सीधे टकराव की भाषा भले न अपनाए लेकिन अपनी चिंता जरूर दर्ज कराता है।

सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी घटना उस बदलती दुनिया की तरफ इशारा करती है जहां जंग अब खुलकर नहीं बल्कि छुपकर लड़ी जा रही है। पहले जंग का मतलब होता था टैंक, मिसाइल और खुला संघर्ष लेकिन अब जंग का मतलब है रास्तों पर नियंत्रण, सप्लाई चेन पर पकड़ और आर्थिक दबाव। जो देश इन तीनों को संभाल लेता है वही असली ताकत बनता है। खाड़ी का इलाका पहले से ही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता रहा है और यहां होने वाली हर हलचल का असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है।

अगर आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां बढ़ती हैं तो इसका असर सीधे आम इंसान की जिंदगी पर भी दिखाई देगा। तेल की कीमत बढ़ेगी, सामान महंगा होगा, सप्लाई में देरी होगी और बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी लेकिन यह सब एकदम से नहीं होगा बल्कि धीरे-धीरे होगा और यही इस तरह की जंग की खासियत है कि यह दिखती कम है और असर ज्यादा करती है।

ममता, मोदी, मुस्लिम और महिला-पश्चिम बंगाल में करो या मरो का चुनाव

संतोष कुमार पाठक

पश्चिम बंगाल में होने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर-शोर से जारी है। राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। इस चुनाव के लिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए यह करो या मरो वाला चुनाव बन गया है। लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन का अंत कर ममता बनर्जी वर्ष 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। वर्ष 2016 में ममता बनर्जी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। वर्ष 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का पुरजोर दावा किया। बीजेपी ने उस चुनाव को कांटे की टक्कर का बना देने में कामयाबी भी हासिल की और नतीजे भी उसके हिसाब से शानदार ही रहे लेकिन ममता बनर्जी उससे कहीं ज्यादा आगे रही। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीटों की संख्या अप्रत्याशित रूप से 3 से बढ़कर सीधे 77 पर तो पहुंच गई लेकिन 48.5 प्रतिशत वोट के बल पर 215 सीटें जीतकर ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बन गईं। इस बार जहां ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। बीजेपी को इस बात का बखूबी अहसास है कि अगर इस बार पार्टी बंगाल में सत्ता में आने से चूक गई तो पार्टी के लिए राज्य में संगठन और कैडर तक बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण के तहत राज्य की जिन 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। उन सीटों पर अब तक तीन करोड़ सात लाख 77 हजार 171 मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें एक करोड़ 84 लाख 99 हजार 496 पुरूष मतदाता है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 75 लाख 77 हजार 210 है। दोनों चरणों को अगर मिलाकर देखा जाए तो महिला मतदाताओं की संख्या 3.33 करोड़ है जो कि पुरुष मतदाताओं के लगभग ही है। इसलिए बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, यह महिला वोटरों के रूख पर ही ज्यादा निर्भर करेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ जहां बीजेपी महिला आरक्षण से जुड़े बिल के लोकसभा में पास नहीं होने का ठीकरा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर फोड़ रही है, वहीं टीएमसी अपने महिला सांसदों की संख्या और महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए बीजेपी को ही महिला विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में सौगातों की बौछार कर दी है। जिसके जवाब में ममता ने पहले से ही चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाने का वायदा किया है। महिला वोटरों के साथ ही राज्य में मुस्लिम मतदाता भी ममता बनर्जी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है और इसमें से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा है। ममता की पार्टी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मुस्लिम वोटरों के ही नाम काटे गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। महिला और मुस्लिम वोटरों के साथ ही ब्रांड मोदी और ममता भी राज्य के जनादेश को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश के जरिए ममता बनर्जी को महिला विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया है, उससे साफ-साफ नजर आ रहा है कि इस देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही बंगाल में भी बीजेपी ब्रांड मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। जबकि टीएमसी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की तरह ही इस बार भी ब्रांड ममता बनर्जी पर ही निर्भर है। पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य, घमासान और चुनावी बयानबाजी से यह साफ-साफ नज़र आ रहा है कि इस राज्य का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव बन गया है।

बच्चे के अंदर दिखें ये बदलाव तो पेरेंट्स न करें नजरअंदाज, हो सकते हैं एंग्जायटी के लक्षण

अगर बच्चा किसी काम को करने से पहले घबराता है, हथेलियों पर पसीना आए या फिर लोगों से मिलने-जुलने से कतराने लगे। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे के इस बदलते व्यवहार के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार बच्चे एंग्जायटी को लेकर बात करना चाहते हैं, लेकिन माता-पिता उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे में अगर समय पर एंग्जायटी के लक्षणों पर ध्यान न दिया जाए और इलाज न किया जाए, तो आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एंग्जायटी के लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं।

बच्चे का गुस्सैल होना - अगर बच्चे में एंग्जायटी की समस्या की समय रहते पहचान न की जाए, तो इसका सीधा असर बच्चे के लिए बिहेवियर पर देखने को मिलता है। बच्चा गुस्सैल हो जाता है किसी भी काम को करने से पहले झुंझलाते या फिर घबराते हैं।

तैयारी के बाद भी एग्जाम में जाने से डरना

एंग्जायटी की समस्या से गुजरने वाले बच्चों के अंदर एग्जाम को लेकर डर बैठ जाता है। अच्छी तैयारी होने के बाद भी उनको लगता है कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कई बार वह परीक्षा न देने के लिए बहाने ढूंढते हैं या फिर उससे बचने का प्रयास करते हैं। अच्छी तैयारी होने के बाद भी वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं।

घर से बाहर जाने में घबराहट

अगर बच्चा घर से बाहर जाने में कतराता है या किसी पार्टी व रिश्तेदार के यहां जाने से बचता है या फिर कई बार शॉपिंग पर जाने से मना करना। बच्चे का स्कूल जाने की इच्छा नहीं होना और न अपने दोस्तों से मिलना।

भूख और नींद कम होना

बता दें कि एंग्जायटी का असर बच्चे की नींद और भूख पर भी देखने को मिलता है।पहले जिन खेलों या एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए बच्चा आगे रहता था, अब उसमें वह हिस्सा लेने से पीछे हट जाता है। या फिर डांसिंग, सिंगिंग या ड्राइंग जैसी मनपसंद एक्टिविटी में मन नहीं लगना।

एंग्जायटी के लक्षण

पेट दर्द या सिरदर्द की शिकायत
जी घबराना या उल्टी होना
सांस लेने में तकलीफ
ज्यादा पसीना आना
ऐसे पहचानें पेरेंट्स

पहले जिन कामों को करने में बच्चा दिलचस्पी दिखाता था, अब उन्हीं कामों को वह बोझ समझने लगा है।

बच्चा अगर किसी काम को करने से पहले ही यह कह दे कि वह मुझसे नहीं होगा।

बच्चे का बार-बार बीमार पड़ना और रात में नींद कम आना।

बच्चे का बाहर जाने से मना करना।

किसी से मिलने-जुलने में कंफर्टेबल फील नहीं करना।

काम को न करने के लिए बच्चे द्वारा नए-नए बहाने बनाना।

जानिए क्या करें पेरेंट्स

बच्चे के व्यवहार में बदलाव देखने के बाद पेरेंट्स उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करने का प्रयास करें। साथ ही यह भी प्रयास करें कि आखिर बच्चा किस बात को लेकर परेशान हो रहा है। इसलिए बच्चे की बात को बेफिजूल मानकर नहीं टालना चाहिए। बच्चे को ऐसे फील कराएं कि आप उनका साथ हर स्थिति में देंगे। बच्चे के आसपास रहें और उनको कंफर्टेबल फील कराने का प्रयास करें। उनकी डाइट का ध्यान रखें। बच्चे की सेहत पर यदि एंग्जायटी का ज्यादा असर नजर आने लगा है तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात करने में बिल्कुल भी देर नहीं करें।

केरल के मुनरो आइलैंड की खूबसूरती देखकर झूम उठेंगे आप, प्रकृति प्रेमियों के लिए है जन्नत

दक्षिण भारत में जब किसी खूबसूरत राज्य में घूमने की बात होती है, तो बहुत सारे लोग केरल का नाम सबसे पहले लेते हैं। केरल दक्षिण भारत का पर्यटन हब माना जाता है। केरल की खूबसूरती हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहां पर स्थित लैगून और बैकवॉटर देखने के लिए लोग केरल पहुंचते हैं। जब भी केरल घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले एलेप्पी, कुमारकोम, मुन्नार, वायनाड, वागामों और त्रिशूर जैसी फेमस जगहों पर जाना चाहते हैं। लेकिन मुनरो द्वीप के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको मुनरो द्वीप की खूबसूरती, खासियत और यहां पर मौजूद कुछ शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

मुनरो द्वीप

केरल के कोल्लम जिले में स्थित मुनरो द्वीप एक अद्भुत और अनोखी जगह है। यह कोल्लम शहर के कुछ किमी की दूरी है। इस द्वीप को कई लोग मुंद्रोथुरुथु के नाम से भी जानते हैं।

केरल में अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर यह द्वीप स्थित है। मुनरो द्वीप राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 90 किमी की दूरी पर है। यह द्वीप एलेप्पी से करीब 87 किमी दूर और कोट्टयम से महज 84 किमी दूर है।

मुनरो द्वीप का इतिहास

मुनरो द्वीप का इतिहास काफी रोचक है। इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम पूर्व ब्रिटिश निवासी कर्नल मुनरो के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि जब कर्नल मुनरो ने देखा कि सिंचाई के लिए आसपास के इलाकों में बहुत समस्या हो रही है, तब इस द्वीप का निर्माण करवाया गया था।

मुनरो द्वीप की खासियत

केरल के साथ-साथ दक्षिण भारत का भी यह एक ऐसा आइलैंड है, जो नदी और झील के किनारे स्थित है। मुनरो द्वीप अष्टमुडी झील और कल्लदा नदी के संगम पर स्थित है। जोकि अपने आप में अनोखा है।

इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि यह केरल का छिपा हुआ मोती है, जो करीब 8 द्वीपों से बना हुआ है। यहां पर स्थित बैकवाटर और लैगून पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

सैलानियों के लिए है खास

मुनरो द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासकर जो सैलानी बैकवाटर और लैगून से प्रेम करते हैं, उनके लिए मुनरो द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह खास जगह है।

मुनरो द्वीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ शांत और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां पर कई पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। मानसून में इस द्वीप की खूबसूरती चरम पर होती है।

आसपास घूमने की जगहें

मुनरो द्वीप के आसपास कई शानदार और मनमोहक जगहें हैं। ऐसे में आप इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहां पर अष्टमुडी झील, वेस्ट एंड ईस्ट कल्लाडा और थेवलक्करा गांव को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कैसे पहुंचे मुनरो द्वीप

बता दें कि मुनरो द्वीप पहुंचना आसान है। इसके पास में कोल्लम रेलवे स्टेशन है, जोकि यहां से 27 किमी दूर है। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे पास त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जोकि 80 किमी दूर है। ऐसे में आप एयरपोर्ट से कैब या टैक्सी करके मुनरो द्वीप जा सकते हैं।

केरल में भी हैं जम्मू-कश्मीर जैसी जगहें, जानें कहां और कैसा है वहां का नजारा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में तनाव का माहौल है. कई लोग अब जम्मू-कश्मीर जाने से डर रहे हैं. ऐसे में इस ठंडे राज्य में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कर रखे थे, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं. इन सभी के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि अगर वो जम्मू-कश्मीर की टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो इस गर्मी के मौसम में भारत के किस राज्य में जाना बेहतर रहेगा. ऐसे में आज इस खबर के जरिए जानिए कि गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी...

केरल के वायनाड जिले में स्थित कलपेट्टा नामक इलाका बेहद शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह है. यह जगह आपको बेहद पसंद आएगी. प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह हिल स्टेशन पर्यटकों को एक नया अनुभव देता है. आइए अब इस जगह के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं.

केरल के बारे में सोचते ही सबसे पहले उनके दिमाग में मुन्नार या थेक्कडी जैसी जगहें आती हैं. दरअसल, ये दोनों ही जगहें लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं. लेकिन केरल में और भी कई नई और अनोखी जगहें . इनमें से एक है कलपेट्टा. जी हां ! हममें से कई लोगों ने अब तक कलपेट्टा के बारे में नहीं सुना होगा. लेकिन यह एक ऐसी जगह है जो लोगों के दिलों को मोह लेती है. यह ऊंची पहाड़ियों और हरे-भरे जंगलों का एक सुंदर मिश्रण दृश्य प्रस्तुत करता है.

कलपेट्टा केरल के वायनाड जिले में स्थित एक जगह है. यहां चारों तरफ हरे-भरे पेड़ और प्राकृतिक सुंदरता है. यहां जाने वाले हर व्यक्ति के लिए यह एक अच्छा अनुभव होगा. यह बहुत ही शांत वातावरण वाली जगह है. यह समुद्र तल से लगभग 780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. पश्चिमी घाटों के बीच स्थित इस जगह पर मौसम हमेशा ठंडा रहता है. गर्मियों में भी ठंड कभी कम नहीं होती. यही कारण है कि यह पूरे साल घूमने के लिए एक आदर्श जगह है.

कलपेट्टा के आसपास मेप्पाडी नामक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चाय के बागान हैं. इन हरे-भरे क्षेत्रों के बीच घूमना एक अद्भुत एहसास देता है. हर पर्यटक इनके बीच के रास्तों पर घूमना और फोटो लेना पसंद करता है. कलपेट्टा से 15 किमी दूर एक खूबसूरत झील है. वहां नाव से यात्रा करना और पक्षियों को देखना बहुत आनंददायक है. इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह प्राकृतिक झील समय बिताने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करती है.

यदि आप कहीं ठंडी जगह जाना चाहते हैं, चाहे गर्मी की छुट्टियों में या मानसून के मौसम में, तो कलपेट्टा सबसे अच्छा विकल्प है. यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसकी प्राकृतिक सुन्दरता के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है. यदि आप कुछ नया देखना चाहते हैं और यातायात और अराजकता से दूर एक शांत, ठंडी जगह में समय बिताना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कलपेट्टा की यात्रा करनी चाहिए.

रोजाना खाली पेट सूखे आंवले और जीरे का पानी पीने से शरीर को मिलेंगे कई फायदे, बदलाव देख रह जाएंगे हैरान

आयुर्वेद में सूखा आंवला पाउडर और जीरे के पानी को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। दरअसल, आंवला और जीरा दोनों ही प्राकृतिक तत्व और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यह शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसके अलावा यह बालों और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको सूखे आंवला पाउडर और जीरे के पानी के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।

ऐसे बनाएं आंवला पाउडर और जीरे का पानी

आंवला पाउडर - 1 चम्मच सूखा
जीरा पाउडर - 1 चम्मच भुना हुआ
पानी - 1 गिलास गुनगुना

इन सभी चीजों को पानी में मिलाकर उबाल लें और फिर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें।

पाचन तंत्र होगा मजबूत

सूखा आंवला पाउडर और जीरे का पानी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। आंवले में फाइबर की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। वहीं जीरा गैस, एसिडिटी और अपच को ठीक करता है। ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट आंवला पाउडर और जीरा पानी पीते हैं, तो इससे पाचन संबंधी समस्या दूर होगी।

इम्युनिटी

आंवला विटामिन सी का मुख्य सोर्स है। यह शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आंवले में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करते हैं। जीरा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। जोकि इंफेक्शन से लड़ने में सहायता करता है। ऐसे में नियमित रूप से यह पीने से सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं कम होती हैं।

वेट लॉस

अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सूखा आंवला पाउडर और जीरा पानी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आंवला मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और जीरा भी एक्स्ट्रा फैट कम करता है। साथ ही यह कॉम्बिनेशन भूख कम करने के साथ ही शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम करने में सहायक है।

डिटॉक्सिफिकेशन में लाभकारी

आंवला और जीरा पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आंवला लिवर को स्वस्थ रखता है और खून साफ करता है। वहीं जीरा भी शरीर के हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार होता है। इसलिए रोजाना सुबह खाली पेट इसको पीने से बॉडी डिटॉक्स होता है और शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है।

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

आंवला में विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह स्किन को ग्लोइंग बनाता है और झुर्रियों को भी कम करता है। वहीं यह पिगमेंटेशन और मुंहासों को भी दूर करता है। वहीं जीरे का पानी भी बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह बालों का झड़ना कम करने के साथ उनको मजबूत बनाता है।

डायबिटीज होगी कंट्रोल

दरअसल, आंवले में क्रोमियम नामक मिनरल पाया जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो वहीं जीरा भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिलता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सीएम सम्राट चौधरी ने पलटा विजय सिन्हा का फैसला

पटना। खबरों के मुताबिक, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अपने पहले कदम में पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश को रद्द कर दिया और पिछले ढाई महीने से निलंबित 224 राजस्व कर्मचारियों को बहाल कर दिया। विजय सिन्हा, जो बिहार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रह चुके हैं, के नेतृत्व में भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए, सिन्हा ने अलग-अलग आदेश जारी कर कम से कम 224 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। हालांकि, बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री चौधरी ने इस आदेश को पलटते हुए 224 अधिकारियों को बहाल कर दिया। यह दूसरी बार है जब उन्होंने पूर्व नीतीश कुमार सरकार के आदेश को रद्द किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में की पहली पूजा

देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में बुधवार को पूरे रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ प्रवेश हुआ, जिसमें भारत और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए धाम का दौरा किया। समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों का पाठ किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली प्रार्थना की और राज्य की जनता की खुशी, समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। कई श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखकर अपार आस्था और आनंद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम, चार धामों के साथ, उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है।

क्या सीएम स्टालिन बचा पाएंगे अपना किला?

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की कोलाथुर सीट फिर से हाई-प्रोफाइल टक्कर का केंद्र बनी है। इस सीट से डीएमके की ओर से खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनावी रण में उतरे हैं। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल 2026 को होने हैं और 04 मई 2026 को मतगणना होनी है। ऐसे में कोलाथुर विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कोलाथुर विधानसभा सीट डीएमके का मजबूत किला है। यहां से डीएमके की ओर से खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चुनावी रण में उतरे हैं। वहीं एआईएडीएमके के प्रत्याशी पी. संथाना कृष्णन भी इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टीवीके ने यहां से वीएस बाबू पर भरोसा जताया है, तो वहीं एनटीके ने Soundara Pandian Louther Seth को चुनावी मैदान में उतारा है। चार प्रत्याशियों के इस सीट पर आमने-सामने होने से यह मुकाबला बहुकोणीय और रोचक बन गया है।

लखनऊ मेयर के आवास का सपा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (एसपी) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की दिवंगत माता के बारे में उनके कथित बयान के विरोध में था। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों द्वारा खारकवाल की टिप्पणियों को आपत्तिजनक बताए जाने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन अखिलेश जी और राहुल जी, जिनकी मां, बहन और बेटी हैं, ने महिलाओं का अपमान किया। यह देश हमारी मां है। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहती हूं कि मैंने अपने भाषण में उनकी मां का जिक्र कहां किया?

तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात

पटना। बिहार की राजनीति में बुधवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाक़ात की। बात सिर्फ मुलाक़ात की ही नहीं है बल्कि तेज प्रताप यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर किये गये पोस्ट को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक पंडित इस मुलाक़ात के मायने निकालने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाक़ात की। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इस मुलाकात को केवल एक औपचारिक भेंट मानने से इनकार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद इस बैठक को जनहित और भविष्य की राजनीति का नाम दिया।

चुनाव आयोग से मल्लिकार्जुन खरगे की शिकायत

कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित रूप से दिए गए बयान को लेकर आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने इसे गंभीर और निंदनीय मामला बताते हुए निर्वाचन आयोग से हस्तक्षेप की मांग की।

मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल दुख और आक्रोश के साथ आयोग के समक्ष पहुंचा। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है।

वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वह पूर्ण आयोग के समक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई निंदनीय टिप्पणियों को उजागर करने के लिए उपस्थित हुईं, जिसमें विपक्ष द्वारा बार-बार अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया गया था। भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बार-बार अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का एक पैटर्न दिखाया है।

सीतारामन ने कहा कि आज हम मतदान आयोग के समक्ष उपस्थित हुए ताकि उन्हें यह अवगत कराया जा सके कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव वाले राज्य में मीडिया को संबोधित करते हुए बेहद निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा है... कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बार-बार अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का एक पैटर्न दिखाया है।

वित्त मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी का समय बेहद संवेदनशील है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि किरण जी ने सही कहा, आज हम पहलगाम हमले की एक सालगिरह मना रहे हैं, जहां निहत्थे नागरिकों को उनके परिवारों के सामने ही मार दिया गया था। आज हम इस घटना की पहली बरसी मना रहे हैं और ठीक उसी दिन की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव वाले राज्य चेन्नई जाते हैं, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बातें कहते हैं।

सीतारामन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत बन गई है कि वे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनिंदा अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और बार-बार ऐसा करते हैं, उनके रवैये में कोई बदलाव या सुधार नहीं आया है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर दिए जा रहे बार-बार के बयानों पर चिंता जताते हुए यह मामला पूरी आयोग के समक्ष उठाया गया था।

सफाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बोले-

मैंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी नहीं कहा: मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर बुधवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने चेन्नई में अपने बयान पर पहले ही सफाई दे दी है। कर्नाटक के बीदर में पत्रकारों से बात करते हुए खर्गे ने कहा कि मैंने चेन्नई में अपने बयान पर सफाई दे दी है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी करार दिया था। व्यापक आलोचना के बाद, खरगे ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को डराते हैं।

भाजपा नेताओं ने खरगे की टिप्पणी की निंदा की और चुनाव आयोग में कड़ी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही माफी की मांग भी की। मंगलवार को कलबुर्गी में, खरगे ने एएनआई को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कभी आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि मोदी सरकार द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजनेताओं और उम्मीदवारों को डरा रहे हैं और इस संबंध में मैंने कहा कि कर आतंकवाद हो रहा है, ईडी छापे मार रही है, आयकर विभाग छापे मार रहा है, सीबीआई छापे मार रही है।

उन्होंने कहा था कि इस आतंकवाद को प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा... वे लोगों को डरा रहे हैं। वे छापों के जरिए लोगों को चुप कराने और उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई में मैंने यही कहा था। इससे पहले, तमिलनाडु चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, खरगे ने एआईएडीएमके की भाजपा को समर्थन देने के लिए आलोचना करके और प्रधानमंत्री मोदी को समानता में विश्वास न करने वाला आतंकवादी बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। यह सब महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े परिसीमन विधेयक की हार के दौरान विपक्षी एकता पर चर्चा के बीच हुआ था।

आलोचना के बाद, खरगे ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा मोदी को आतंकवादी कहने का नहीं, बल्कि उन्हें राजनीतिक विरोधियों को डराने वाला व्यक्ति बताने का था। उन्होंने कहा कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) लोगों और राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं... मेरा मतलब यह है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ईडी, आयकर और सीबीआई जैसी संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं। वह परिसीमन को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

ममता राज में 7000 इंडस्ट्रीज बंद!

टीएमसी ने 30 लाख युवाओं की नौकरी छीनी: योगी

कोलकाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर ज़ोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि उसके शासन में पश्चिम बंगाल में उद्योगों का भारी पतन हुआ है और उसने एक राष्ट्रीय आर्थिक अगुआ के तौर पर अपनी जगह खो दी है। बड़ा बाज़ार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य, जो कभी उद्योग, शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब वर्षों के कुशासन के कारण पिछड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के दौरान 7,000 से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गईं।

उन्होंने कहा कि बंगाल, जो कभी कई सेक्टरों में सबसे आगे था, अब सबसे नीचे पहुँच गया है और साथ ही यह भी जोड़ा कि हज़ारों एमएसएमई यूनिट्स भी बंद हो गई हैं, जिससे लगभग 30 लाख युवाओं की नौकरियाँ चली गई हैं। उन्होंने दावा किया कि इस गिरावट ने राज्य को एक ऐसी जगह में बदल दिया है, जिसे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ का क़ब्रिस्तान बताया।

टैगोर की विरासत को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया

नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के जोरासांको स्थित पैतृक घर का ज़िक्र करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ऐतिहासिक घर के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर लगाए गए थे, जिसे उन्होंने टैगोर की विरासत का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर भारत माता और महान सांस्कृतिक हस्तियों की झलक दिखनी चाहिए, न कि राजनीतिक प्रदर्शन।

बंगाल में राजनीतिक बदलाव की मांग

वंदे मातरम के 150वें वर्ष का ज़िक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को अपनी खोई हुई शान वापस पानी होगी और दावा किया कि ऐसा केवल सरकार बदलने से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को विकास लाने और उद्योगों को फिर से ज़िंदा करने के लिए, जिसे उन्होंने डबल-इंजन सरकार कहा, उसकी ज़रूरत है।

संस्कृति, पहचान और धर्म पर ज़ोर

योगी आदित्यनाथ ने भाषा और सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी चिंता जताई, और आरोप लगाया कि बंगाली परंपराओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। उन्होंने टीएमसी पर धार्मिक जुलूसों पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया और कहा कि दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे त्योहारों पर बेवजह पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने धार्मिक भावनाओं पर टीएमसी के रवैये पर भी सवाल उठाए, और अयोध्या में राम मंदिर के विरोध का ज़िक्र किया।

खेल
प्रमुख समाचार

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज

मुंबई। महेंद्र सिंह धोनी और विल जैक्स गुरुवार रात वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बड़े मुकाबले के लिए वापसी करने को तैयार दिख रहे हैं। गुरुवार को होने वाले मुकाबले धोनी की मौजूदगी संघर्ष कर रही सीएसके टीम के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। 44 साल के इस अनुभवी खिलाड़ी ने मंगलवार को वानखेड़े में अभ्यास किया। उन्होंने करीब आधे घंटे तक विकेटकीपिंग की और फिर 30 मिनट तक बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

प्री-सीजन शिविर के दौरान पिंडली में खिंचाव से उबर रहे धोनी में किसी भी तरह की परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिखे और वह मैच के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए। सीएसके इस समय अंक तालिका में आठवें स्थान पर है, उसने 6 मैचों में से केवल दो मैच जीते हैं, ऐसे में धोनी की वापसी टीम के बल्लेबाजी क्रम को बहुत जरूरी स्थिरता और अनुभव दे सकती है।

वहीं मुम्बई इंडियंस की बात जाए जैक्स के लंबे समय से इंतजार हो रहे आगमन से टीम में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने 2026 टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था और चार बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। पहले छह मैच न खेल पाने के बाद वह अब टीम से जुड़ गए हैं। उन्होंने सोमवार शाम को वानखेड़े में ट्रेनिंग की और मंगलवार को रात की रोशनी में होने वाले सेशन के लिए भी लौटे, जहाँ उन्होंने बल्ले और गेंद, दोनों के साथ काफी समय बिताया। जैक्स के टीम में शामिल होने से मुंबई इंडियन का संतुलन मजबूत हो गया है; वह मध्यक्रम में ताकत देने के साथ-साथ ऑफ-स्पिन गेंदबाजी का एक उपयोगी विकल्प भी देते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 756 अंक टूटा निफ्टी 24378 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार (22 अप्रैल) को गिरावट में बंद हुए। इसी के साथ बाजार में तीन ट्रेडिंग सेशन से जारी बढ़त का सिलसिला थम गया। रुपये में गिरावट ने भी बाजार पर दबाव डाला। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 79,019 पर खुला। जबकि मंगलवार को यह 79,273 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 78,442 अंक के निचले स्तर तक गया। अंत में 756.84 अंक या 0.95 फीसदी की गिरावट लेकर 78,516.49 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 24,470 पर खुला। जबकि मंगलवार को यह 24,500 के ऊपर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 24,352 अंक के इंट्रा-डे लो और 24,515 अंक के इंट्रा-डे हाई तक गया। अंत में 198.50 अंक या 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,378 पर बंद हुआ।

रियल एस्टेट में पूंजी निवेश जनवरी-मार्च में 72% बढ़ा

नई दिल्ली। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जनवरी-मार्च में पूंजी निवेश सालाना आधार पर 72 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 5.1 अरब डॉलर रहा। रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई ने यह जानकारी दी। जनवरी-मार्च 2025 में रियल एस्टेट क्षेत्र में पूंजी प्रवाह 2.9 अरब डॉलर और अक्टूबर-दिसंबर 2025 में 3.3 अरब डॉलर रहा था। सीबीआरई ने भारत बाजार निगरानी, पहली तिमाही 2026 -निवेश रिपोर्ट बुधवार को जारी की। इसमें जनवरी-मार्च में आए निवेश की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, इस रिकॉर्ड पूंजी निवेश में डेवलपर की मुख्य हिस्सेदारी रही। इसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) का स्थान रहा जिन्होंने किराये पर देने वाले कार्यालयों और खुदरा परिसंपत्तियों के निर्माण एवं अधिग्रहण में निवेश किया।

अल्पकालिक उतार-चढ़ाव सहित एफडीआई निकासी पर नजर

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निकासी और विनिमय दर में बदलाव जैसे अल्पकालिक उतार-चढ़ाव चक्रीय प्रकृति के होते हैं और इन पर करीबी नजर रखी जा रही है। गवर्नर ने न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा सोमवार को आयोजित एक गोलमेज बैठक में यह बात कही। इस संबंध में अगले दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मल्होत्रा ने नियामकीय ढांचे को सरल बनाने, कारोबार सुगमता बढ़ाने, विदेशी निवेशकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने और घरेलू व विदेशी बाजारों के एकीकरण को मजबूत करने के लिए जारी सुधारों का उल्लेख किया। इस गोलमेज बैठक में वित्तीय संस्थानों, निवेश कंपनियों और नीतिगत क्षेत्र से जुड़े 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जापान का 2025-26 में व्यापार घाटा 1700 अरब येन

तोक्यो। जापान का वित्त वर्ष 2025-26 में व्यापार घाटा 1700 अरब येन (10.7 अरब डॉलर) रहा। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि लगातार पांचवें वित्त वर्ष में व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि हुई जबकि आयात केवल 0.5% बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति के जापान और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए ऊंचे शुल्क वैश्विक मोटर वाहन विनिर्माताओं और अन्य उद्योगों के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं। गत वित्त वर्ष में अमेरिका को जापान का कुल निर्यात 6.6% घटा जबकि मोटर वाहन निर्यात में 16% की गिरावट आई। मार्च में जापान का व्यापार अधिशेष एक साल पहले की तुलना में हालांकि 26% बढ़ा, जो निर्यात क्षेत्र के पिछले झटकों से उबरने का संकेत है।

कोरिया की इंजीनियरिंग, भारत का बाजार: दूसरी लहर का फायदा उठाने का समय

शिव सिद्धांत कौल

रविवार, यानी 19 अप्रैल को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली जे म्युंग भारत पहुंचे। यह करीब आठ वर्षों के बाद किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह यात्रा ऐसे समय में हुई, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अहम मोड़ से गुजर रही है। भारत और कोरिया, दोनों देशों के व्यावसायिक जगत को उम्मीद है कि यह यात्रा आपसी रिश्तों को एक नई दिशा देगी, जहां साझेदारी रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के मजबूत स्तंभों पर आधारित होगी।

पिछले वित्त वर्ष में 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते' (सीईपीए) के दम पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब कोरियाई कंपनियां महज विदेशी कंपनियां नहीं रहीं, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट ढांचे का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। 2024 के अंत में हुंडई मोटर इंडिया का 3.3 अरब डॉलर का आईपीओ और फिर अक्तूबर 2025 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की 1.4 अरब डॉलर की पब्लिक लिस्टिंग इसका साफ संकेत है कि ये कंपनियां अब अपनी आर्थिक सफलता और बाजार की उपलब्धियों में भारतीय निवेशकों को भी साझेदार बना रही हैं। अगर आर्थिक रिश्ते इस साझेदारी की 'ईंटें' हैं, तो सांस्कृतिक जुड़ाव वह 'गारा' है, जो इन ईंटों को मजबूती से जोड़ता है। आज भारत में कोरियाई संस्कृति की लहर तेजी से फैल चुकी है। कोरियाई पॉप संगीत, ड्रामा, सौंदर्य प्रसाधन और खान-पान भारतीय युवा संस्कृति में व्यापक रूप से फैल गए हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या, छात्रों का आदान-प्रदान, और

सियोल में भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों तथा भारत में कोरियाई प्रवासियों के गतिशील समुदाय लोगों के बीच ऐसा जुड़ाव पैदा कर रहे हैं, जो व्यावसायिक एकजुटता से कहीं अधिक व्यापक और गहरा होगा। अब समय आ गया है कि हम इस साझेदारी की 'दूसरी लहर' का लाभ उठाएं। हमारे सामने अवसरों का अंबार है, लेकिन इन्हें भुनाने के लिए हमें एक आधुनिक और उन्नत कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। अपने व्यापार की वास्तविक क्षमता को उजागर करने और भारत के संरचनात्मक व्यापार घाटे को दूर करने के लिए, हमें सबसे पहले ऐसे उन्नत सीईपीए की आवश्यकता है, जो संतुलित और न्यायसंगत व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा दे। हमें रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी आपूर्ति शृंखला, महत्वपूर्ण खनिजों और हरित ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में रणनीतिक जुड़ाव स्थापित करने होंगे।

दूसरा, भारत कोरियाई उद्योगों को अपने विनिर्माण क्षेत्रों में चल रही नई क्रांति का पूरा फायदा उठाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। संरचनात्मक सुधारों, बेहतर नीतियों और 'विकसित भारत' के संकल्प से प्रेरित 'मेक इन इंडिया' पहल आज ऐतिहासिक अवसर बन चुकी है। दक्षिण कोरिया की सटीक इंजीनियरिंग और हार्डवेयर में विशेषज्ञता, जब भारत के विशाल, कुशल मानव संसाधन और बड़े घरेलू बाजार से जुड़ेगी, तो ऐसी वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं तैयार हो सकती हैं, जो किसी भी भू-राजनीतिक झटके का मजबूती से मुकाबला कर सकती हैं। तीसरा, अब समय है कि हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ताकत का भी पूरा उपयोग करें। भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताएं व दक्षिण कोरिया की हार्डवेयर में पकड़ एक-दूसरे की पूरक हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का विस्तार और एआई तकनीकों का इस्तेमाल विकास की रफ्तार को तेज कर सकता है। इससे भाषा जैसी बाधाएं भी कम होंगी, जिन्होंने अब तक, खासकर एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग को धीमा किया है। जैसे-जैसे कंपनियां इस महत्वपूर्ण सम्मिलन की तैयारी कर रही हैं, उम्मीद है कि एक उन्नत और संतुलित सीईपीए समझौता जल्द ही अंतिम रूप लेगा, जिससे 2030 तक 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह उद्योगों की अगुवाई में एक साझा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण कार्यबल का गठन, रक्षा, सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री व ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को गति देगा।

30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र! कांग्रेस ने सत्र के औचित्य पर उठाए सवाल

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पारित नहीं हो पाने पर 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहुत किया जा रहा है। सत्र के दौरान अधिनियम के पारित नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।

विधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार की ओर से 30 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित करने का आग्रह हुआ। विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कितने दिन का सत्र होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आधी आबादी को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि उनके अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा।

वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर कहा कि कांग्रेस घटिया और निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह की भाषा का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। कांग्रेस अपनी गिरती हुई राजनीति का परिचय दे रही है।

अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के राजनीतिक पतन और घटियापन को दर्शाता है।

सचिन तेंदुलकर के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सुरक्षा सवालों पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी

कि नक्सलवाद खत्म हो। नक्सली कांग्रेस के पाले-पोसे लोग रहे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि बस्तर में शांति स्थापित हो। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बस्तर के युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है।

आदिवासी समाज के धर्मांतरण करने वालों की डी-लिस्टिंग की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि धर्मांतरण प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सरकार बनने के बाद इस पर सख्त रुख अपनाया गया और मौजूदा कानूनों को और कठोर बनाया गया है। विधानसभा से भी सख्त कानून पारित कर कार्रवाई तेज की गई। समाज को भी आगे आकर धर्मांतरण रोकने में सहयोग करना होगा।

वहीं विधानसभा के विशेष सत्र पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान प्रजातंत्र में नहीं है। अगर है तो विपक्ष को भी एक दिन का मौक़ा दें। उनकी पोल खोलकर रखेंगे। किस तरह से प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया है, महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। उन सबके बारे में बताया जाएगा। जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, उसे लागू करना चाहिए। 2028 और 2029 के चुनाव में उसे लागू करना चाहिए।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के सवाल पर शिव डहरिया ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों का सम्मान करती है। अरुण साव नरेंद्र मोदी के लिए टिप्पणी कर रहे होंगे। प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं।

सचिन तेंदुलकर के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी जाना था। सभी कार्यक्रम में उनके साथ रहना था। ऐसा लग रहा है कि सुरक्षागत कारणों से उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया है। यह बोलते है नक्सल मूवमेंट हमने खत्म कर दिया।

हकीकत यह है कि नक्सली मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए डर में मुख्यमंत्री नहीं जा रहे है। सुरक्षा कारणों से सचिन के दौरे में कटौती की गई है। ऐसी जानकारी मिली है कि यह नक्सल मूवमेंट को देखते हुए किया गया है। इससे सरकार के कार्यों पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार झूठी सरकार है। लगता है मुख्यमंत्री दिल्ली के कंट्रोल में चल रहे हैं। जनदर्शन लगाया करते थे उसके लाखों आवेदन पेंडिंग हैं। उसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। हेल्पलाइन से कोई फ़र्क़ पड़ने वाला नहीं है। दिखावे की राजनीति बीजेपी करती है। जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए बरगलाने का काम सरकार कर रही है।

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र अंश की रायपुर में हुई पूजा

बलौदा बाजार में दर्शन को लेकर तैयारियां तेज

रायपुर। राजधानी रायपुर में बुधवार को विमतारा हॉल में रोटरी क्लब ऑफ रायपुर सुप्रीम द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से सोमनाथ से आए पवित्र ज्योतिर्लिंग अंश की विधि-विधान से पूजन-अर्चन की गई। इस आध्यात्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पंडितों के मार्गदर्शन में संकल्प लेकर भगवान शिव की आराधना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा, जहां उपस्थित लोगों ने गहन आध्यात्मिक अनुभव की अनुभूति की।

रोटरी क्लब ऑफ रायपुर सुप्रीम के अध्यक्ष एस.के. श्रीवास्तव और सचिव सुनील अग्रवाल ने बताया कि यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस पावन आयोजन का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि क्लब भविष्य में भी सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा।

इधर, बलौदा बाजार में भी सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग अंश के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारी के अनुसार, यह पवित्र शिवलिंग अंश 27 अप्रैल को बलौदा बाजार पहुंचेगा, जहां दशहरा मैदान स्थित यज्ञस्थली में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा।

आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े आयोजकों के अनुसार, इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले आयोजन को लेकर शिवभक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराए जा सकें।

आर्ट ऑफ लिविंग की जिला समन्वयक किरण वर्मा ने बताया कि लगभग एक हजार वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किए थे। उस दौरान अग्निहोत्री पंडितों ने शिवलिंग के अंश को सुरक्षित रखा और निरंतर उसकी पूजा-अर्चना करते रहे।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1924 में कांची के शंकराचार्य ने यह संकेत दिया था कि लगभग 100 वर्षों बाद यह पवित्र धरोहर ऐसे संत को सौंपी जाएगी, जिनके नाम में 'शंकर' होगा। उसी क्रम में यह शिवलिंग अंश गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने लोककल्याण की भावना से इसे भक्तों के दर्शन हेतु विभिन्न स्थानों पर भेजना प्रारंभ किया है।

किरण वर्मा ने कहा कि 27 अप्रैल को इसका बलौदा बाजार आगमन होना क्षेत्र के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

आयोजन से जुड़े लोगों का मानना है कि यह अवसर क्षेत्र के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इससे लोगों में धर्म एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर मोतीलाल वर्मा, अनामिका अग्रवाल, लता साहू, अंकित तिवारी, सुरेन्द्र वर्मा, प्यारेलाल सेन, डॉ. जे. एन. केसरवानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से बदली तस्वीर

रायपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' कोंडागांव जिले में सकारात्मक बदलाव की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में कोण्डागांव जिले के फरसगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गट्टीपलना की निवासी श्रीमती सिदाय नेताम आज एक सफल कृषक उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी सफलता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है।

फरसगांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम गट्टीपलना की श्रीमती सिदाय नेताम 'शिव शक्ति स्व-सहायता समूह' से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्हें बैंक लिंकेज के माध्यम से 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसने उनके जीवन में परिवर्तन की दिशा तय की।

मिशन के तहत कार्यरत टीम एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर के माध्यम से उन्हें आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन जैसी उन्नत विधियों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग की जानकारी भी प्रदान की गई। इन तकनीकों को अपनाते हुए सिदाय नेताम ने टमाटर, करेला एवं पॉपकॉर्न मक्का की खेती प्रारंभ की। उन्होंने अपनी कृषि

गतिविधियों में कुल 1 लाख 50 हजार रुपये का निवेश किया। उनकी मेहनत, लगन और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग का परिणाम यह रहा कि उन्हें 3 लाख 60 हजार रुपये की कुल आय प्राप्त हुई, जिससे 2 लाख 10 हजार रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ।

यह सफलता केवल आर्थिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उनके आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में वे अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि सखी के रूप में कार्य करते हुए अन्य महिलाओं को आधुनिक खेती, जैविक खाद के उपयोग तथा कृषि यंत्रों के समुचित उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया है। आज वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं तथा बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर रही हैं।

जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल से जिले में ऐसे अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं, जहां महिलाएं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संगठित होकर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति भी सशक्त हो रही है। यदि ग्रामीण महिलाओं को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वे कृषि एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। सिदाय नेताम की सफलता इसी का सशक्त प्रमाण है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन के अवसर प्रदान करना है। जिले में मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। सिदाय नेताम की यह सफलता उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक है। आज वे न केवल अपने परिवार को सशक्त बना रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी हुई हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

राज्यपाल डेका से नो प्लास्टिक कैंपेन की ब्रांड एंबेसडर शुभांगी आप्टे ने की मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में नो प्लास्टिक अभियान की ब्रांड एंबेसडर श्रीमती शुभांगी आप्टे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने रायपुर नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और जनजागरूकता गतिविधियों की जानकारी दी। श्रीमती आप्टे ने बताया कि अब तक वे स्कूलों, बैंकों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 55 हजार से अधिक कपड़े की थैलियों का वितरण कर चुकी हैं, ताकि लोगों को प्लास्टिक उपयोग से दूर किया जा सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि में 6 पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया है। साथ ही शासकीय अस्पतालों में जरूरतमंद माताओं और नवजात शिशुओं के लिए जच्चा-बच्चा किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यपाल ने उनके सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। ज्ञातव्य है कि श्रीमती आप्टे नगर निगम के स्वच्छता अभियान की ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

आजादी के बाद पहली बार दर्जनों टोलों के विद्युतीकरण को मिली मंजूरी

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से आजादी के बाद पहली बार सूरजपुर जिले के वनांचल क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में बड़ी पहल साकार हुई है। भटगांव विधानसभा क्षेत्र के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों और आश्रित टोलों के विद्युतीकरण के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। ** दर्जनों गांवों में पहुंचेगी बिजली, बदलेगा जीवन स्तर मंत्री श्रीमती राजवाड़े की पहल पर कोल्हुआ-पुराना स्कूलपारा, खासपारा, जमतीपारा और बोकराटोला-2 के विद्युतीकरण को मंजूरी दी गई महुली-हरिजनपारा, खासपारा-1 व 2, पांडोपारा, पोखरापारा, स्कूलपारा, पहेतापारा और पहाड़पारा में बिजली विस्तार का कार्य होगा। करोटी-खासपारा, इमलीडीह, पोड़ीडोल, पोरतेपारा, परसापारा और गुलरडांडपारा जैसे क्षेत्रों में रोशनी पहुँचेगी। चोंगा-मधवानीपारा, आमपारा, खासपारा और श्यामपारा के निवासियों को बिजली की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कछवारी (पांडोपारा, स्कूलपारा), खैरा (रेडियापारा-1 व 2), नवडीहा (मेन रोड) और कछिया (नवडीहा चौक) में भी विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा।

रायपुर के इस रहवासी कॉलोनी में लगी भीषण आग

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के

पवन विहार कॉलोनी, न्यू राजेंद्र नगर में बुधवार की सुबह सात बजे भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शॉप संचालक की लापरवाही यह आग लगी। बताया जाता है कि गिफ्ट दुकान में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे। फायर उपकरण का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आग बुझाने के जो उपकरण रहने चाहिये थे, वो मौक पर मौजूद नहीं थे। बड़ी बात यह है कि यह दुकान न्यू राजेंद्र नगर स्थित पवन विहार रहवासी कॉलोनी में स्थित है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी ओर दुकान संचालक विशाल कुकरेजा का कहना है कि आग लगने से करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

पैंगोलिन बेचने 2 तस्कर पहुंचे रायपुर, वन विभाग ने पकड़ा

रायपुर। वन विभाग की टीम ने रायपुर में 50 करोड़ की पैंगोलिन के साथ दो तस्करों को पकड़ा है। दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के रहने वाले है। जब्त पैंगोलिन का कुल वजन 20 किलो बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम दोनों तस्करों के खिलाफ आगे की जांच कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए आरोपियों का नाम प्यारेलाल गोपचे और गोखन हलदार है। जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि भाठागांव के पास रावांभाठा, वालफोर्ट सिटी रायपुर के पीछे एक झुग्गी झोपड़ी में दो आरोपीसंदिग्ध रूके हुए हैं। दोनों के पास जिंदा पैंगोलिन है। वन विभाग ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया। ग्राहक बनकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तस्करों को पैंगोलिन दिखाने को कहा। दोनों आरोपियों ने जिंदा पैंगोलिन दिखाई, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ बताई थी। सौदा होने के बाद कर्मचारी ने बाहर इंतजार कर रहे वन विभाग की टीम को इशारा कर झोपड़ी में आने को कहा। टीम जैसे ही पहुंची तो आरोपी उन्हें देखकर घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें टीम ने दौड़ाकर पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 किलो वजनी पैंगोलिन जब्त की गई।

मंत्रालय में सिविल सर्विस डे मनाया गया

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सिविल सर्विस दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। शासन की अधिक से अधिक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी सेवा के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन की करीब 750 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के तहत अधिसूचित किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 21 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देशभर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं विभागों को पुरस्कृत किया जाता है। पूर्व मुख्य सचिव श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा ने सिविल सर्विस दिवस के मौके पर प्रशासन की विविध क्षेत्रों में कार्य करने एवं महत्वता के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य सचिव एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह भी विशेष रूप से शामिल हुए। सुशासन एवं अभिसरण विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने मुख्यमंत्री हेल्प लाईन के बारे में लोगों द्वारा विविध माध्यम से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत दर्ज कराने एवं निराकरण के प्रबंधन एवं सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति

19 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

रायपुर। शहर में सुगम यातायात एवं आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर जिले में 19 प्रवेश मार्गों से शहर के भीतर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-01 एवं रिंग रोड-02 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों से मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ हो गया है, जो 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों

के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

प्रतिबंधित प्रवेश मार्गों में तेलीबांधा थाना के सामने चौक, कैनाल रोड प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, महावीर नगर चौक रिंग रोड 01, राजेंद्र नगर चौक रिंग रोड 01, पचपेड़ी नाका चौक रिंग रोड 01, संतोषीनगर चौक रिंग रोड 01, भाठागांव चौक रिंग रोड 01, कुशालपुर चौक रिंग रोड 01, रायपुरा चौक रिंग रोड 01, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग रिंग रोड, गोगांव तिराहा रिंग रोड नं. 02, गोंदवारा तिराहा रिंग रोड नं. 02, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड स्थित व्हीआईपी तिराहा एवं एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।

शहर में पिछले कुछ समय से भारी वाहनों के कारण मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग रहा था। इससे स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से ट्रैफिक जाम कम होगा। सड़क हादसों में कमी आएगी। बाजार और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा रायपुर शहर के भीतर यातायात सुगम होगा

धर्मांतरण रोकने समाज के लोगों को आना होगा आगे: अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लेकर कहा कि इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को कांग्रेस की गिरती हुई भाषा की मर्यादा और घटिया मानसिकता से दिया गया बयान कहा है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जो स्थिति बनी है वह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि धर्मांतरण राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है। पूर्व में ऐसे मामले सामने आने के बाद हमारी सरकार ने मौजूदा कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की है। वहीं अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है। इससे राज्य में धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि, समाज को भी धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना होगा। समाज में भी लगातार जागरूकता आ रही है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आगे कहा कि, जिस प्रधानमंत्री ने देश से आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त किया, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए निम्न स्तर की भाषा का उपयोग बेहद दुर्भाग्यजनक है। साव ने कहा कि ये कांग्रेस की गिरती हुई साख को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पाइपलाइन से हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने की योजना लेकर आई है। ये योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू की जा रही है। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में एजेंसियों को काम दिए गए हैं, उन एजेंसियों ने तेज गति से काम करना प्रारंभ कर दिया है। आगामी समय में घरों में सीधे पाइपलाइन से रसोई गैस मिलेगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.